Title: Further discussion regarding terrorist attack on Parliament House raised by Shri Mulayam Singh Yadav on the 18th December, 2001 (concluded).

11.09 hrs.

श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) : मोहतरम आलीजनाब स्पीकर साहब, पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना टैरेरिस्ट हमले की जिस कदर मजम्मत की जाये, उसको जितना भी कंडैम किया जाये, कम है। लेकिन यह बात वाजे होनी चाहिए कि हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क है, we are a great nation और इस अजीम मुल्क को डराया नहीं जा सकता, खौफजदा नहीं किया जा सकता, मरऊब नहीं किया जा सकता। यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेज, वॉच एंड वार्ड और दीगर अमलों ने जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर पार्लियामेंट की हिफाजत की है ,यह काबिले तहसीन है, यह काबिले कद्र है। हम इन तमाम को सेल्यूट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, यह टैररिस्ट का हमला नाकाम बना दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक जबर्दस्त एचीवमेंट है। लेकिन जहां इस हमले को नाकाम बनाया गया, वहां हमें इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए कि यह हमला मुमकिन भी हो सका है। इस पर इसलिए गौर करना चाहिए कि जरूरी तदावीर, जरूरी इकदामात पर गौर किया जा सके। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि किस्मत ने बड़ा साथ दिया है। कुछ कोइंसीडेंट, इत्तफाकात हुए, जिसने बड़ा साथ दिया, वरना तो क्या हालात बनते, उसको सोच कर ही दिल दहल जाता है। यह पांच या छः टैररिस्ट दाखिल हो सके, बारूद से भरी हुई गाड़ी अंदर आ सकी, वाइस प्रेजीडेंट जाने की तैयारी में थे। उनका गार्ड, उनका अमला अलर्ट था। टैररिस्ट में आपस में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। गाड़ी बंद पड़ी, वायर की खामी की वजह से कोई धमाका नहीं हुआ। इस सबके लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इन इत्तफाकात पर भी गौर करना और जरूरी कदम उठाना होगा। यह एक बेहद अहम् और संगीन मामला है। तो खामियां हुईं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।

अब यहां पर होम मिनिस्टर साहब ने एक बयान पेश किया। यह बयान किस किस्म का है, जब बयान पढ़ रहे थे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि किसी छोटे-मोटे अखबार की प्रिलीम्नरी रिपोर्ट, इबतिदाई रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई जा रही है। किसी अहम् पहलू की तरफ, कोई निशानदेही उसके अंदर नहीं पाई जा सकी। वाक्यात के अहम् पहलू, जिसके बारे में इतने कयास-आराइयां की जा रही हैं, यह बयान खामोश है। किस दरवाजे से दाखिल हुए, उस सिलसिले में क्या गौर किया गया, बयान खामोश। आर्मी कब बुलाई गई, बुलाई गई या नहीं बुलाई गई, कब वापस हुई, क्या हालात रहे, बयान खामोश। सी.बी.आई. को इन्वेस्टीगेशन में मुलव्वस किया गया, इन्वॉल्व किया गया या नहीं और कौन से पहलू इनके सुपुर्द किए गए, बयान खामोश। इतने दिनो तक जैसे पता चला है साजिश होती रही। पोटो भी आपके पास था, क्या तदावीर की गईं, बयान खामोश। तकरीबन हर पहलू पर वाक्यात के पहलू पर बयान खामोश। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर क्या किया जा रहा है, खुशी है, इत्मीनान है कि आपने पाकिस्तान के हाईकमीश्नर को बुलाकर खबरदार किया। लेकिन इसके अलावा क्या सोचा जा रहा है, डिप्लोमैटिक फ्रंट पर बयान खामोश। आगे की कार्रवाई के बारे मे कुछ एक-दो पुराने बयान होम मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर के दे दिए गए हैं, जिससे कोई निशानदेही नहीं होती।

मैं यहां तक कहता हूं कि इस बयान से ज्यादा अहम तो प्राइम मिनिस्टर का वह बयान रहा जो उन्होंने बीजेपी के मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट के यहां दिया है। वह फोरम शायद इनको पार्लियामेंट के इस फोरम से ज्यादा अहम दिखाई दिया। किस तरह इस फोरम को डील किया जा रहा है? आज जब यह बात मैं कह रहा हूं तो स्पीकर साहब, एक बात बहुत साफ और वाजह तौर पर कह देना चाहता हूं और वह यह है कि इन मामलात के सिलसिले में हुकूमत फैसला करे कि वह क्या कदम उठाना चाहती है। इन्शाह-अल्ला, हम सब हुकूमत का इस सिलसिले में साथ देंगे, उसमें कोई दूसरी बात नहीं आ सकती। फैसला आपको करना है। गौर करके करना है। तदब्बुर के साथ करना है। मामलात के तमाम पहलुओं considering all the aspects and consequences , हर बात पर गौर करके आपको फैसला करना है लेकिन जो कोई फैसला आप करेंगे, मुल्क पूरे इत्तिहाद के साथ हुकूमत के साथ रहेगा, इस बारे में किसी के पास कोई शक-औ-शुभा न रखे लेकिन यहां बयान से हमें कुछ मालूम नहीं हो रहा है कि हुकूमत किस तरह से सोच रही है बल्कि हुकूमत को शायद दूसरों को पेश करना पड़ा कि वह बार-बार हमको यही यकीन दिलाये और मैम्बर्स ट्रेजरी बेंचेज से उठते रहे और स्टेटमेंट की खामियों औऱ कमज़ोरियों को दूर करते हुए ईवान को यकीन दिलाते रहे कि जो कुछ भी जरूरी होगा, वह कार्रवाई की जाएगी। बहसूरत इस पर गौर किया जाये, पूरे कंसल्टेशंस किये जाएं, सारे कंसीक्वेंसेज नताइज़ को सारे पहलुओं को सामने रखा जाये। हमारा मशविरा एहतियात का मशविरा है लेकिन हमारा मुकम्मल साथ हुकूमत के फैसले के साथ रहेगा। जब मैं यह कहता हूं तो इस बात पर मुल्क मुत्तहद है, टैरेरिज्म के मुकाबले के बारे में इत्तिहाद है लेकिन इस इत्तिहाद और यूनिटी को कायम रखना हम सबका फर्ज है। इसमें हुकूमत का फर्ज कुछ ज्यादा है कि यह इत्तिहाद कायम रखा जाये, इसकी हिफ़ाजत की जाये। कंट्रोवर्शियल मैटर्स मुतानाजा मामलात आज न उठाए जाएं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि इफ्तिलाकी मामिलात से बचकर इस यूनिटी और इत्तिहाद की हिफ़ाजत की जाये। यह बहुत गलत होगा कि टैरेरिज्म और दहशतगर्दी को इस्लाम या मुसलमानों के साथ जोड़ने की कोशिश की जाये। खास एहकामात जारी किये जाएं, पूरी तबज्जोह की जाए कि दहशतगर्दी के खात्मे की आड़ में, terrorism का खात्मा करने के बहाने की आड़ में अकलियतों को, मुसलमानों को परेशान और सताया न जाये। मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि आज हमें एन्गजाइटी है, तशवीश है। Anxiety is writ large on the faces of the Muslims and the minorities. इसके लिए कि पिछले तजुर्बे चाहे वह किसी भी हुकूमत के जमाने में हुए हों, वे तजुर्बे हमें याद हैं और हम यह भी जानते हैं कि आज इख्तिदार में गालिब अनसर उनका है। जो फिरकाबराना फास्सिस्ट राज्य के नज़रिये पर यकीन रखते हैं।

The predominant element in the ruling coalition consists of those who believe in communal fascist raj. इसीलिए यह तशवीश है कि अब आप अपने मुल्क के लोगों के इत्मानान को जीतने की कोशिश करें और यह देखें कि इत्तिहाद बरकरार रहे, बाकी रहे। कितने इख्तिलाफी मामलात 'पोटो' से लेकर अयोध्या, बंग्लादेश, immigrants, मदरसे, कितने मामलात यहां उठाये गये। मदरसों में दहशतगर्द पनाह ले रहे हैं, हमें बताया गया है और वहां पर दहशतगर्दी की तालीम दी जा रही है। एक मिसाल पेश नहीं की जा सकी। हमने कई बार कहा कि इसकी कोई लिस्ट है तो टेबल के ऊपर दुनिया के सामने रख दी जाये लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं रखा गया। एक प्रोपोगेंडा है जो बराबर चलकर एक अफसोसनाक सूरत-ए-हाल बयान किया जा रहा है कि इंडो-नेपाल बॉर्डर का जिक्र हुआ कि बड़ी तादाद के अंदर मदरसे खुल गये हैं। स्पीकर साहब, मैं याद दिलाऊं कि होम कंसलटेटिव कमेटी में मैंने आदाद-औ-शुमार पेश किये थे कि इंडो-नेपाल बॉर्डर पर There is no significant increase in the number of Mosques or *Madrasas*. मैंने आदाद और शुमार पेश किया। 800 कि.मी. का यह जो बॉर्डर है, 10-10-,15-15 कि.मी. चले जाओ, कोई मस्जिद, कोई मदरसा नहीं मिलता। कोई सिगनिफिकेंट इंक्रीज नहीं हुई, यहां यह मालूम है।

MR. SPEAKER: Banatwalla, please conclude.

SHRI G.M. BANATWALLA : Yes, I will be concluding. पिछले तीस सालों के अंदर, जब कि आबादी बढ़ती है तो जरुरतें बढ़ती हैं लेकिन पिछले तीस सालों में मस्जिदों की तादाद बढ़कर 74 से सिर्फ 146 के करीब हुई है। पिछले तीस सालों में मदरसों की तादाद 61 से बढ़कर 123 के करीब आबादी के लिहाज से पहुंची है। मैंने जब होम कंसलटेटिव कमेटी में आदाद-औ-शुमार और भी ज्यादा रखे तो एक अजीब सी बात मुझे बतलाई गई। होम सैक्रेटरी ने मुझे जवाब दिया कि बनातवाला जी, "जब हम यह कहते हैं कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर मदरसों की बड़ी तादाद आ गई है तो हमारा मतलब इंडो-नेपाल बॉर्डर की नेपाल साइड से है, इंडिया की साइड से नहीं है।" एक अजब सा जवाब कंसलटेटिव कमेटी के अंदर दिया गया लेकिन यहां एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। हुकूमत सख्ती के साथ इस प्रोपोगेंडा से पेश आये। यहां अयोध्या का मसला, 12 मार्च की धमकी बराबर दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की कोई परवाह नहीं है लेकिन हुकूमत खामोश है। संघ परिवार

को एक खुली छूट है कि यह जोâ€¦(व्यवधान) यह मुखतलिफ मसाईल मैं कहता हूं।â€¦(व्यवधान) इखतिलाफी मामले को आगे न लाया जाये। इत्तिहाद और देश की यूनिटी को बरकरार रखा जाये और इन्शाह-अल्ला इत्तिहाद के साथ हम बराबर कंधे से कंधा मिलाकर जो टैरेरिज्म आता है, इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं आने पाएगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज जिस विाय पर चर्चा हो रही है, यह विाय न केवल राट्रीय महत्व का है, बल्कि अन्तरराट्रीय महत्व का गम्भीरतम विाय है। सबसे पहले मैं 13 दिसम्बर को संसद भवन पर जो आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया और हमारे सुरक्षाकर्मी जो शहीद हुए या वाच-एंड-वार्ड के कर्मचारियों ने बलिदान देकर, जान देकर संसद को बचाने का काम किया, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदन व्यक्त करता हूं। इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर साहसिक काम किया है और निश्चित रूप से वह प्रशंसा के काबिल है। मैं समझता हूं, जिस बहादुरी और साहस के साथ कर्तव्य निठा का परिचय दिया है, उसके संदर्भ में जितना भी कहा जाए, संसद भवन पर हुए हमले की जितनी निन्दा की जाए, उतनी कम है। आतंकवादी अपनी योजना को पूरे तरीके से अंजाम नहीं दे पाए, यदि आरडीएक्स डैटोनेटर का तार नहीं टूटा होता, तो तबाही का मंजर कुछ और ही होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं उस समय इसी लाबी में मौजूद था और हमारे बहुत से साथी माननीय सदस्य मौजूद थे। श्री राम नगीना मिश्र जी मौजूद थे और अध्यक्ष महोदय, आप भी अपने कक्ष में थे। मैं उस समय जो हालात देखे, मैं उसको बयान करना चाहता हूं। अफरा-तफरी मची हुई थी, एक असुरक्षा का वातावरण संसद में माननीय सदस्यों के बीच था और उसी समय माननीय गृह मंत्री जी अपने कक्ष से निकलकर सैन्ट्रल हाल से होते हुए, लाबी से होते हुए संसदीय कार्य मंत्री के कमरे में जा रहे थे। उस समय रामनगीना मिश्र जी यहीं लाबी में जिस तरह से पैनिक हुए थे, मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूं। उन्होंने गुस्सा दिखाया और एक एसएलआर जवान, जो हाउस बन्द होने के बाद यहां उपस्थिति होता है, को उन्होंने देखा। वे जिस तरह से पैनिक हुए, मैं उसको बयान नहीं करना चाहता हूं। प्रभुनाथ सिंह जी ने बताया, कुछ इस तरह की अफवाह चली कि कुछ आतंकवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन एक आतंकवादी सुरक्षा घेरे को तोड़कर अन्दर घुस आया है। गेट नं.4 पर कहा जा रहा था कि ऐसी जगह खोजिए, जिससे हम लोग बचें, क्योंकि अब कोई बचने वाला नहीं है। गोली, बमबारी चल रही है, क्रास-फायरिंग हो रही है और गोलियां चलने के बाद जो परिदृश्य बना, मैं उसको बयान नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यह महसूस करने की बात है। अध्यक्ष महोदय, आप भी अपने कमरे में चैनल पर देख रहे थे और माननीय गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विजय कुमार मल्होत्रा, प्रियरंजन दासमुंशी जी, जो दृश्य 12 बजे देखा गया था, उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। मैं साहस के साथ कहना चाहता हूं कि जहां सच्चाई है, वहां साहस होना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी, यदि सुरक्षा में कोई चूक हुई है, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यह मामला पूरे देश की राट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। पूरे देश की सम्प्रभुता का सवाल है और इस सवाल पर हिचकने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ है, इसको स्वीकार करना चाहिए।

महोदय, मैं साहस के साथ हो रही बहस के नजरिए का जिक्र करना चाहता हूं। बहस जिस पटरी पर होनी चाहिए, जिस स्तर पर होनी चाहिए, जिस ऊंचाई पर होनी चाहिए, उस ऊंचाई को सब लोग अपनी-अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत ही दुखद बात है। मैं तकलीफ के साथ इस बात को कहना चाहता हू, बहस की दिशा हिन्दू-मुसलमान नहीं है। बहस की दिशा होनी चाहिए, विदेशी आतंकवादियों ने देश की सुरक्षा को चुनौती देने का काम किया है। विदेशी आतंकवादियों ने हमारी संसद पर, जो देश की सबसे बड़ी संस्था है, लोकतन्त्र की सबसे बड़ी इमारत है, उस पर हमला किया है। इस विाय पर बहस होनी चाहिए। बहस की दिशा हिन्दू-मुसलमान नहीं होनी चाहिए। विदेशी आतंकवादी, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो, जो भी हो, उन्होंने हमारे देश की लोकतन्त्र पर, लोकतन्त्र की जो सबसे बड़ी इमारत है, उस पर हमला किया है। बहस की दिशा इस दिशा में होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सेम्पूर्ण राट्र को इस हमले को लेकर, राट्रीय सुरक्षा के मामले में एकजुट होने की जरूरत है।

आज सदन में एक प्रस्ताव लाने की जरूरत है, एकजुट होकर, एक स्वर से आतंकवादी गतिविधि के खिलाफ और आतंकवादी गतिविधि को शह देने वाले जो भी देश हैं, उनके खिलाफ भी एकजुट होने की जरूरत है। उनके खिलाफ एक स्वर में हमें इकट्ठा होने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, कट्टरपंथी, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो उग्रवादी - उन आतंकवादियों को जिन लोगों ने ठहराने का काम किया है, क्या वे मुसलमान हैं? जिस घर में वे ठहरे थे, उसका मकान-मालिक कौन था, जिलानी, न जाने कितने दिनों से यह काम कर रहा था। इतने समय तक हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थीं - यह सवाल है? यहां कहा गया कि बड़े तर्क और लोजिक के जरिए, बड़ी बहादुरी से सुरक्षाकर्मियों नें मुकाबला किया, उन्हें घुसने नहीं दिया - इसमें बहादुरी नहीं देखनी चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमारी कोई चूक हुई है, इस चूक को स्वीकार करना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए कि ऐसी चूक क्यों हुई। हमारा देश उदारवादी है, उदारता और धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की शान है, उसमें उग्रवाद और आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आज देश के नागरिक की सुरक्षा के सवाल पर मैं कहना चाहता हूं, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो आज बड़ी भारी संवेदनशीलता, कूटनीति की बात कर रहे हैं, हिन्दुस्तान को उपदेश दे रहे हैं। ये उपदेश देने वाले वही देश हैं, जिन्होंने गुड़ नहीं खाया है वे गुड़ छोड़ने का आदेश दे सकते हैं। क्या दो तरह की नीति आतंकवाद से निबटने की होगी। आतंकवाद, उग्रवाद के खिलाफ दो तरह का कटघरा होगा - एक अमेरिका और इज्रायल के लिए होगा और एक हिन्दुस्तान के लिए होगा, तीसरी दुनिया में रहने वाले देश के साथ होगा, यह विचार करने का विाय है। संयम बरतने का उपदेश आया है, उन्होंने संयम क्यों नहीं बरता था, इस पर विचार करने की जरूरत है। दो तरह की नीति को मानने की जरूरत नहीं है, आज देश को जरूरत है - "खुदी को करो बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है।" हमें अपनी ताकत को इतनी मजबूती से आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शित करना चाहिए कि दुनिया हमारी बुलन्दी को स्वीकार करें और समझे।

महोदय, मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, आप एक एक्शन प्लान बनाइए, ठीक है, लेकिन उसे सोच-समझ कर बनाएं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक्शन प्लान बनाएं। यदि आपके डिप्लोमेटिक मैथड्स पर सारे विकल्प एगजास्ट नहीं हुए हैं तो उसे एगजास्ट करने की कोशिश कीजिए, जो भी डिप्लोमैटिक मैथड्स हैं उनका इस्तेमाल करिए। देश की जनभावना और सुरक्षा में निश्चित रूप से रणनीति बना कर, पूरे देश को इकट्ठा होकर आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करने में कोई हिचक न करें, क्योंकि राट्रहित का सबसे बड़ा संवेदनशील मामला है।

महोदय, इस सदन में कुछ नेता मस्तिक प्रधान हैं, हम ह्रदय प्रधान हैं, इस सवाल को भी घेरे में बांध कर विचार करना उचित नहीं होगा। मैं मस्तिक प्रधान और राट्रीय नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया में भारत से एक स्वर निकलना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी कार्यवाही हो, उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। आतंकवाद के लिए कोई जगह हमारे हिन्दुस्तान, लोकतांत्रिक देश में संप्रभुता पर हमला करने की कोई गुंजाइश न बचे। इसके लिए जो भी कार्यवाही करनी पड़े, वह करनी चाहिए। गृह मंत्री जी, केवल कविता और बयान देने से आतंकवाद का मुकाबला नहीं होगा, इसका मुकाबला करने के लिए जो भी रणनीति बनाएं, उसमें देश की भावना को समझें। केवल सदन में ही संपूर्ण देश नहीं है, सदन के बाहर भी लोग हैं। हम लोग प्रतिनिधि हैं, लेकिन सदन के बाहर करोड़ों लोगों की भावना आतंकवाद को मसलने और कुचनने की है। हमें आतंकवाद का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करना है, इसलिए जनभावनाओं को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसमें कोई कमजोरी न करे।â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, अन्य माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं, अब आप समाप्त करिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा।

इस देश में आतंकवादियों की गतिविधियां लाल किले से लेकर कश्मीर विधान सभा तक और फिर संसद भवन पर हमला तो हमारे प्रजातंत्र पर हमला है। हम किसका

इंतजार कर रहे हैं? मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक आदमी अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। उसको एक व्यक्ति ने मारा तो वह बोला कि मेरे बेटे को मार तब तुझे देख लूंगा। उस व्यक्ति ने बेटे को भी पीट दिया। फिर उसने कहा कि मेरी पत्नी को मार तब तुझे देख लूंगा। उसने उसकी पत्नी को भी पीट दिया। इस तरह से उसने सारे परिवार को पिटवा दिया। फिर वह बोला कि मेरे परिवार को तो पीटा दिया है आगे किसी को पीटा तो देख लेंगें । हम कहां जा रहे हैं। अब देखने की जरूरत नहीं है। अब तो संपूर्ण रूप से कार्रवाई करने की जरुरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सब लोग ऊपर की तरफ ही देख रहे हैं। चेयर की तरफ कोई नहीं देख रहा।

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, संसद पर जो हमला हुआ है वह देश के अस्तित्व और प्रजातंत्र पर हमला है। इससे देशवासियों को बहुत जबरदस्त धक्का लगा है। इससे एक बहुत गंभीर परिस्थिति पैदा हो सकती थी लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मचारियों और उनके सहयोगियों ने जो हिम्मत दिखाई वह काबिले-तारीफ है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और जिन्होंने अपनी जान दी, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। जो बात कल से यहां शुरु है और मैंने कई साथियों के विचार सुने और कुछ सुरक्षा की कमियों की बात सुनी। गृहमंत्री जी को कुछ कमियों को स्वीकार करने के भी सुझाव दिये गये। मुझे लगता है कि जिन परिस्थितियों में यह हमला हुआ, उनको देखने के बाद सुरक्षा में कमियां निकालना ठीक नहीं होगा। गाड़ी एम्बैस्डर थी, संसद का पास लगा था, ऊपर लाल-बत्ती लगी थी, होम-मिनिस्टरी का स्टीकर लगा था। इसलिए सुरक्षा कर्मियों द्वारा गाड़ी रोकना आसान न था। वह कैसे रोक सकते थे। आज संसद सदस्यों को सोचने की आवश्यकता है कि लाल बत्ती लगाने का अधिकार किसको है? सदन के जितने सदस्य लाल-बत्ती लगाकर आते हैं क्या उनको लाल-बत्ती लगाने का अधिकार है? हम खुद ही कानून को अपने हाथ में लेंगे, लाल-बत्ती लगाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे और किसी सुरक्षा कर्मी ने रोका तो सदस्यों को कितना गुस्सा आता है इस बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सुरक्षा-व्यवस्था को सबसे पहले हमें स्वीकार करना होगा। जिस दिन हम इसको ठीक तरह से स्वीकार करेंगे तभी सुरक्षा-कर्मियों को यहां की सुरक्षा ठीकर करने में शक्ति मिलेगी।

13 दिसम्बर के बाद पिछले दो-चार दिनों में पूरे देश में एक अलग हवा पैदा करने की कोशिश हो रही है। कुछ राजनैतिक पार्टियों, कुछ संगठनों और कुछ नेताओं में एक सांप्रदायिक ज्वार पैदा करने की तैयारी शुरु की है। मुझे लगता है कि इस सांप्रदायिक ज्वार से किसी समाज को अलग करने की कोशिश देश के हित में नहीं है। हमें इस समय जो राट्रहित की बात है वही करनी पड़ेगी और अगर आतंकवादी शक्तियों के साथ हमें संर्घा करना है तो इस देश के सब लोगों को इकट्ठा करने की तैयारी और मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।

जो परिस्थिति पैदा हुई, उसमें यहां बहुत सी बातें सामने आईं। कई संगठनों ने सरकार को कोई सूचना दे दी, किसी ने सुझाव दिया इसके लिए पड़ोसी देशों को जिम्मेदार ठहराकर उन पर हमला करने की आवश्यकता है। कई लोगों ने कुछ और सुझाव दिये।

11.41 hrs. (Shrimati Margaret Alva in the Chair)

लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की परिस्थिति में सरकार को जो उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इस नतीजे पर जिस दिन सरकार पहुंचेगी, तब सरकार को हम लोगों की तरफ से पूरी तरह से सहयोग देने की आवश्यकता है। उन्होंने क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इस पर सदन में सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमारा नुकसान हो जायेगा। हम एक मैच्योर्ड डेमोक्रेसी चलाने वाले देश के प्रतिनिधि हैं। इस समाज में परिपक्वता है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसकी चर्चा सदन में नहीं हो सकती, इसके लिए मंत्रिमंडल है। प्रधान मंत्री जी को आवश्यकता पड़ेगी तो वह कुछ और साथियों से सलाह ले सकते हैं और समझदारी से देश के हित की बात को मद्देनजर रखते हुए कदम उठा सकते हैं । आज सिर्फ इस बात की आवश्यकता है कि देशवासियों की आत्म शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग इस सदन की मार्फत एकता दिखायें।

सभापति महोदय, दुनिया में उस देश की इज्जत होती है जो देश अपनी हिम्मत दिखाता है, अपनी शक्ति दिखाता है। दुबले लोगों के मुंह से अहिंसा की भााा को दुनिया कभी स्वीकार नहीं कर सकती। मगर यह अहिंसा की भााा, हमले की भााा या जवाब देने की भााा का आधार चाहिए। इस बारे में धैर्य से सोचने की आवश्यकता है। परिस्थिति का अभ्यास गम्भीरता से करने की आवश्यकता है और फिर समझदारी से सोचकर इस पर हम लोगों को कदम उठाने होंगे। मैं इस सदन की तरफ से सरकार को कहना चाहता हूं कि देश के हितों की रक्षा करने के लिए जो कुछ कदम आप उठायेंगे, उन पर आपको हम सबका सहयोग मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं।

SHRIMATI SONIA GANDHI (AMETHI): Madam, this Session will go down in the annals of our parliamentary history because of the dastardly attack which took place on the 13th of December. It was not merely an attack on the magnificent edifice, our Parliament House, it was an attack on a magnificent institution, the symbol of all those values that we cherish, the symbol of our parliamentary democracy. Democracy, in our vicinity, the meaning of this word, the meaning of democracy, can never be understood. In our vicinity, they can never pride themselves in such an institution. On a number of occasions, when attempts were made to establish democracy, those attempts have been invariably stepped upon and crushed by the heavy military boot. In this House and outside, we remain beholden to and we salute all those in the Security Department of Parliament, the paramilitary forces and the Delhi Police who laid down their lives in the line of duty on that dreadful day.

The task before the Government and before all of us belonging to different political parties is to ensure that their families are given the support they deserve from a grateful nation.

Madam, the incident, which took place on the 13th December, uncovers many issues relating to the security of the nation and the security of our people. I sincerely hope that the Government will look into and share with the nation the reasons why the terrorists could make all preparations unhindered and actually enter into the precincts of Parliament and literally knock at the doors of Parliament House, despite, of course, prior intimation.

11.45 hrs. (Mr. Speaker *in the Chair)*

I regret to point out that the Government's statement on the incident is more notable for conspicuous omissions rather than for new revelations. It is obvious that the security arrangements in Parliament and in other numerous sensitive places need to be reviewed and revamped.

Sir, at this critical juncture, the need of the hour is for the Government and for all political parties to rise above partisan considerations. The need of the hour today is for all concerned to desist from using this occasion to raise contentious issues that divide our plural society. This is a moment when the entire country must stand together in solidarity. The responsibility for creating that solidarity lies mostly on the shoulders of the Government.

I wish to assure the Government, through you, Mr. Speaker, Sir, that the Congress Party will back the Government in its effort to track down and bring to justice terrorists who threaten the nation's integrity today. We also believe that the Government must keep in touch and must consult and must interact with all other political parties. On key strategic issues, we believe, it is necessary to think through all the pros and cons.

Finally, we feel that much greater efforts are required at this moment to mobilise world opinion in our favour. Since we have been at the receiving end of terrorism for so many years culminating, of course, with the dreadful incident on the 13th of December, we should certainly be able to embark upon a very concerted diplomatic offensive and garner the full support of the international community for our nation's just cause.

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, सदन ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा है जिसको लेकर पक्ष और प्रतिपक्ष की विभाजक रेखाएं धुल जाती हैं, मिट जाती हैं, धुँधली तो कम से कम पड़ ही जाती हैं। इस स्थिति में जो न पक्ष में हैं, न विपक्ष में हैं, निपक्ष हैं, उनकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए जो देश को सही दिशा दे, देश के मनोबल को बढ़ाए।

मुझे कल चंद्र शेखर जी का भाषण सुन कर महाभारत के मैदान में खड़े हुए अर्जुन की याद आ गई। युद्ध हो या न हो - यह प्रश्न नहीं है। किन परिस्थितियों में युद्ध होगा, होना चाहिए, क्या उसकी जरूरत भी है या नहीं - यह चर्चा का विषय है। कोई भी देश में युद्ध नहीं चाहता।

मैंने एक कविता लिखी थी 'जंग न होने देंगे' लेकिन उसी के बाद कारगिल की जंग हो गई। अगर देश तैयार न होता और केवल 'जंग न होने देंगे', इसी कविता में खो जाता, तो देश के साथ हम बड़ा अन्याय करते। हम वहां शान्ति का संदेश लेकर गए थे लेकिन सफलता नहीं मिली। अब कहा जाता है कि आप गए क्यों। बड़ी मुश्किल है - न जाएं तो कहते हैं कि आप जाते क्यों नहीं और जाएं तो कहते हैं कि आप गए क्यों। लेकिन इस चर्चा में सकारात्मक दृटिकोण उपस्थित किया गया है।

मैं सभी दलों के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा मैंने शुरू में कहा, यह समय ऐसा नहीं है कि हम एक लकीर पीटते जाएं। सब मिल कर रास्ता निकालें, इस बात की आवश्यकता है। यह प्रयास होता रहा है कि सबसे चर्चा हो। अब संसद से जुड़ी हुई घटनाएं जिस तरह से घटीं, उनके बारे में जब तक पूरी जानकारी इकट्ठी नहीं हो जाती, सरकार और प्रशासन उस काम में लगा था, तब तक जो कुछ मीडिया में आ रहा था, जो कुछ समाचार पत्रों में आ रहा था, उससे अधिक और कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का जो विचार हमेशा कार्यान्वित किया जाता है, उसमें देर हुई। उसके बाद छुट्टियां थीं, लेकिन सम्पर्क बना रहा। गृह मंत्री जी इस संबंध में विस्तार से प्रकाश डालेंगे। सदन के सामने सचमुच एक गंभीर परिस्थिति है। अभी तक आतंकवाद मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर तक सीमित था। अब उसने संसद भवन की चौखट को खटखटाया है। हम बधाई दे रहे हैं सुरक्षा बल के उन जवानों को, वाच एंड वार्ड के जवानों को, जिन्होंने प्राणों की बलि चढ़ा कर संसद भवन की रक्षा की।

आतंकवादी यहां तक कैसे पहुंचे, यह जांच का विषय है। इसको गहराई में जाकर देखना होगा, लेकिन इस कारण हमारे प्रशासन ने, हमारे सुरक्षा बल ने और संसद के वॉच एंड वार्ड ने जो बलिदान दिया, जो त्याग किया और जिस तरह की दृढ़ता दिखाई, उसका मूल्यांकन कम नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि सदन में किसी के मन में यह भावना है कि जो भी घटना हुई है, उसका राजनैतिक लाभ कैसे उठाया जाये।

जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि यह राजनीति का वक्त नहीं है, राष्ट्र के अस्तित्व को चुनौती दी गई है, हमारी अस्मिता को ललकारा गया है। संसद भवन क्यों, देश में और भी स्थान हैं। सोच-समझ कर संसद भवन को चुना गया, क्योंकि जो आतंकवादी हैं, वे भी समझते हैं कि यह संसद गणतंत्र भारत का ह्रदय है तथा सारे देश का प्रतिनिधित्व करती है, जो देश की एकता की धुरी है, जो लोकतंत्र की गारण्टी है, जो सब को साथ लेकर चलने का एक महान प्रयत्न है, इस पर प्रहार करो। यह काम सोच-समझ कर किया गया है। मैं नहीं समझता कि यह अनायास हुआ है। मैं नहीं समझता कि जो आतंकवादी बंदूकें लेकर आये थे या आत्महत्या की तैयारी करके आये थे और जिन्होंने उनको भेजा था, उन्होंने इस सवाल को गहराई से नहीं सोचा होगा। उन्होंने सोच-समझ कर यह खतरनाक कदम उठाया है। यह एक चुनौती है और इस चुनौती का सारे देश को सामना करना होगा।

इस चर्चा में जो भाषण हुए हैं, उसके लिए मैं माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं। श्री शिवराज पाटिल ने एक रचनात्मक भाव से अपनी बातें कहीं, लेकिन उनके भाषण से एक बात का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, सदस्यों ने भी उसको सुना था। श्री पाटिल के शब्दों को मैं उद्धृत कर रहा हूं:-

> "महोदय, इस सदन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जब पहले कुछ कदम उठाये गये थे तो हम लोगों ने उसका विरोध किया, ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। आज हमें कम से कम यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। इस सदन की सुरक्षा का जो प्लान बनाया गया था, उस पर पूरी तरह से एक्शन नहीं हुआ है।"

यह बड़ी खुशी की बात है कि स्पीकर साहब ने आज सुबह बैठक में कहा कि जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हुआ, उसके बाद उन्होंने एक कमेटी एपाइण्ट की है, वह कमेटी रिपोर्ट देने जा रही है, उस पर अमल किया जायेगा और इस सदन को सुरक्षा दी जायेगी। कठिनाइयां थीं, अभी भी रुकावटें हैं।

12.00 hrs.

अभी देश को असुरक्षा के वातावरण में किस तरह से व्यवहार करना, किस तरह से अपनी बात कहना, इसका पूरा अभ्यास नहीं हुआ है। शायद इसका कारण हमारा जीवन की ओर देखने का दृटिकोण है। एक दिन मरना तो है ही, इस जीवन को बचाने के लिए सौ उपाय करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यह दृटिकोण सही नहीं है। एक-एक जान की कीमत है। आतंकवादी अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए एक भय पैदा करना चाहते हैं । हमें उन मंसूबों को विफल करना है। सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं, उनका दृढ़ता से पालन होना चाहिए। इस प्रश्न पर लगातार आपस में चर्चा होती रहे, पक्ष और विपक्ष के बीच में नहीं, देश की सर्वोच्च संस्था के प्रतिनिधि के रूप में, पार्टी की रेखाओं को मिटा कर। सुरक्षा का सवाल सर्वोपरि है। लेकिन सदन और संसद की सुरक्षा के साथ-साथ देश की सुरक्षा का सवाल भी जुड़ा हुआ है। एक संकट है और संकट जिन्होंने पैदा किया है, वे एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं।

अब हमें उपदेश दिए जा रहे हैं कि हम संयम से काम लें। हमने कब संयम से काम नहीं लिया है। सचमुच में हमारे संयम को हमारी दुर्बलता समझा गया। हमारा देश लोकतंत्र है। जन भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। उसके साथ क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, इसका विवेक भी आवश्यक है। कोई देश में लड़ाई का जोर पैदा

नहीं कर रहा है, करना भी नहीं चाहिए। युद्ध और शांति के फैसले उत्तेजना में नहीं होते। समग्र परिस्थिति पर विचार करके, सब उपायों को काम में लाते हुए, जो-जो विकल्प हैं, उन सबका विवेचन करते हुए जो नीति बनेगी, वह सारे देश के हितों को ध्यान में रख कर बनेगी। उसमें सबका सहयोग लिया जाएगा। ऐसा निर्णय पार्टी अकेले नहीं कर सकती है। वह देश का निर्णय होगा।

मैं कांग्रेस के सदस्यों को बधाई देता हूं । मैंने प्रियरंजन दासमुंशी जी का भााण सुना। मैंने और भी भााण सुने। सरकार के पक्ष को उमर अब्दुल्ला ने बड़े प्रभावी ढंग से रखा। सचमुच में जो भी कदम उठाया जाएगा, वह राट्र के हितों को सर्वोपरि रख कर उठाया जाएगा। मुलायम सिंह जी को इस सम्बन्ध में किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम आतंकवाद की चर्चा करते हुए सारे मसले पर चुनाव को हावी हो जाने दें, यह ठीक नहीं है। चुनाव होंगे, समय पर होंगे। देश में जो लोकतंत्र है, वह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए संसद को निशाना बनाया गया है। सोची-समझी साजिश के अनुसार, यह आशा की गई थी कि यह देश टूट जायेगा, बिखर जायेगा। पाकिस्तान में कुछ ऐसे तत्व हैं जो पुराने इतिहास की बात करते हैं और सारे देश पर, सारे हिन्दुस्तान पर झंडा फहराने की घोाणाएं करते हैं। एक बार जब देश का बंटवारा हो गया, हमने उसे स्वीकार कर लिया।

जब मैं लाहौर गया था और मीनार-ए-पाकिस्तान पर मुझे जाने का अवसर मिला तो मुझे सलाह दी गई थी कि मैं न जाऊं लेकिन मैंने कहा कि नहीं, यह गलत बात होगी। मैं उस पर गया और मैंने कहा कि हमें एक ऐसा पड़ौसी चाहिए जो उन्नति करे, जो विकास करे और जो शक्तिशाली हो। कभी-कभी दुर्बलतम में से भी दुस्साहस पैदा होने की भावना होती है। पाकिस्तान इस मनोवस्था से ग्रसित है कि भारत ने देश के बंटवारे को स्वीकार नहीं किया। यह गलत है। जनरल मुशर्रफ से भी मैंने कहा था कि हमारे लिए वह अध्याय बंद हो गया लेकिन यह बताइए कि आपने देश के बंटवारे को स्वीकार किया है या नहीं? बंटवारा दुर्भाग्यपूर्ण था मगर हो गया। हम उसके विरोधी थे। आज हम उस पर अमल कर रहे हैं क्योंकि वह राट्र की नीति बन गई है। पाकिस्तान में इस तरह के तत्व सक्रिय हैं और पाकिस्तान की सरकार भी जानती है और हम भी जानते हैं। इसीलिए इस कांड के बाद हमने पाकिस्तान से कहा है कि जो आतंकवादी संगठन इस दुस्साहस के कार्य में शामिल हैं, जिन्होंने इसका संगठन किया, योजना बनाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी लेकिन हम केवल कूटनीतिक तरीके पर भरोसा करके नहीं बैठे हैं, विश्व के जनमत को भी बना रहे हैं, जैसा सुझाव दिया गया है और इस सवाल पर जनमत हमारे साथ है, यह आत्मविश्वास, भरोसा हमें होना चाहिए। इस बीच में मैंने कई देशों की यात्राएं की हैं। भारत की ओर दुनिया एक भरोसे की नजर से देख रही है। भारत का लोकतंत्र एक वर्द्धमान लोकतंत्र है। भारत चुनौतियों का सामना कर सकता है, इसकी अनुभूति बढ़ रही है लेकिन आतंकवाद का मुकाबला हमें अपने बल पर करना पड़ेगा, अपनी शक्ति से करना पड़ेगा। हमारी स्थिति के बारे में संसार के सभी देशों को परिचित किया गया है। वे स्वीकार करते हैं कि आपको आत्म-रक्षा के लिए कदम उठाने का पूरा अधिकार है, इजाजत है लेकिन फिर कहते हैं कि जरा सोच-समझकर करिए। हम सारे कदम सोच-समझकर ही उठा रहे हैं। भविय में भी जो कदम उठाएंगे, उन्हें पूरी तरह से सोच-समझकर, उनके हर पहलुओं पर विचार करके उठाएंगे लेकिन हमें संयम का उपदेश देने वाले जरा हमारे पड़ौसी से भी बात करें, पड़ौसी से पूछें कि उनका खेल कब तक चलेगा? उन्हें पड़ोसी की आवश्यकता है, तो पड़ोसी की आवश्यकताओं में एक आवश्यकता यह है कि आतंकवाद को समाप्त करना होगा। इसके लिए अंतरराट्रीय गठबन्धन हुआ है। दुनिया के अधिकांश राट्र उसमें शामिल हैं। भारत में जो आतंकवाद हो रहा है, उसके लिए किस प्रमाण की जरूरत है? संसद भवन पर लगी हुई गोलियों के दाग, संसद भवन के बाहर आतंकवादियों की पड़ी हुई लाशें, उनके पाकिस्तानी होने का सत्य, यह अपने आप में सबूत है। अपने आप में प्रमाण हैं। मिलकर जांच करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे राट्र की सुरक्षा और राट्र की सर्वप्रभुता को चुनौती दी गई है। हम इसका सामना करेंगे और हम आशा करते हैं कि विश्व के जितने सजग राट्र हैं, उनका हमें समर्थन मिलेगा। हम किसी से यह आशा नहीं करते कि वे हमारी तरफ से लड़े, हम किसी से यह आशा नहीं करते कि वे हमारे पक्ष में मैदान में कूद पड़ें। हमने पहले भी कहा था और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आतंकवाद का खात्मा हम अपने बल पर करेंगे। लेकिन दुनिया के और देशों को भी तय करना है कि आतंकवाद अलग-अलग नहीं हो सकता है। उसकी परिभााा अलग-अलग नहीं हो सकती है। आतंकवाद को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। एक देश में आतंकवाद का एक रूप है और दूसरे देश में किसी और तरह का, ऐसा नहीं माना जा सकता है। आतंकवाद की समाप्ति के लिए विश्व में अभियान चल रहा है। जो कुछ उस दिन हुआ, वह आतंकवाद का खुला प्रदर्शन है। हम विश्वास करते हैं कि अन्य देश इस संबंध में हमारी भावनाओं को समझेंगे और हमें अपना समर्थन देंगे। आतंकवाद से हम पहले भी लड़ चुके हैं। पंजाब में हम आतंकवाद पर विजय भी प्राप्त कर चुके हैं। एक ऐसी परिस्थिति थी कि पंजाब के भविय के बारे में आशंकायें हो रही थीं। एक ऐसी स्थिति पैदा हुई थी कि देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी, देश की अखण्डता खतरे में पड़ जाएगी। इस तरह की आशंकायें जग गई थीं। लेकिन दृढ़ता से कदम उठाये गये और आतंकवाद को कुचला गया। आज पंजाब में शांति है, भाई-चारा है। पंजाब के लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आतंकवाद से हम निपटना जानते हैं और निपटेंगे। लेकिन इस मौके पर दुनिया के देश भी कसौटी पर कसे जा रहे हैं। उनकी कथनी में और उनकी करनी में कितना अंतर है, यह भी उजागर हो रहा है। मापदंड अलग-अलग नहीं हो सकते हैं। आतंकवाद मापने का मापदंड एक ही होगा।

भारत एक लोकतन्त्रवादी देश है। बहुदलीय लोकतन्त्र हमारे यहां हैं। मैं जब विदेश में गया और मैंने विदेशी मेहमानों को बताया कि अफगानिस्तान से हमारा बहुत पुराना संबंध है। विदेश मंत्री के नाते मैं दो बार अफगानिस्तान गया था। । हमने वहां अस्पताल शुरू किया है। हम और सहायता देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तालिबान के आने के बाद सब परिस्थितियों को एक माध्यम में बदल दिया गया, लोग शोक में डूब गए। इसलिए तालिबान को समाप्त करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनका हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने भारत की संसद पर हमला किया है, अनेक माननीय सदस्यों ने इसकी भलीभांति विवेचना की कि उस दिन पता नहीं क्या हो जाता। आतंकवाद से लड़ने के लिए जो तैयारियां की गई हैं, वह भी एक बड़ा कारण था। आतंकवादी जो चाहते थे, वह पूरा नहीं हुआ। उन तैयारियों को हम अनदेखा न करें, कमियों की ओर इशारा करें। किस तरह से कमियां दूर की जाएं, इसके लिए सुझाव आमंत्रित हैं, लेकिन यह प्रश्न पक्ष और विपक्ष का नहीं है। देश में शांति और भाईचारा रहे, जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसे लेकर कोई उसका लाभ उठाए, इस समय अगर कोई भी संगठन या दल वैमनस्य पैदा करने की बात करता है, सम्प्रदायों के बीच में भेदभाव बढ़ाता है तो वह देश का अहित करता है। इस तरह की कार्रवाइयां बर्दाश्त नहीं होगी। लोग सद्बुद्धि से काम लेंगे, इसकी हम आशा करते हैं। यह परीक्षा का काल है। शायद उस दिन हम लोग इसीलिए बच गए कि आने वाले काल में हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। मुझे विश्वास है कि जिस वातावरण में सदन में चर्चा चल रही है, वह इस वातावरण को और भी बलशाली करेगा। सारी दुनिया, सारे देश हमारी ओर देख रहे हैं। दलगत राजनीति चलेगी, वह तो अपनी जगह है, लेकिन इस देश की विशेाता है कि जब-जब संकट की घड़ी आती है तो सारा देश मतभेद भुला कर एक हो जाता है और जो भी खतरा पैदा होता है उसका मिलकर सामना करता है।

महोदय, मैं जब प्रतिपक्ष में था तो मैंने बंगलादेश की आजादी के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को जो बधाई दी थी। वह मेरी भावनाएं नहीं थीं बल्कि हम सब लोगों की भावनाएं थीं। हमने बहुत संयम दिखाया। अब हम कूटनीतिक तरीके से समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, और भी विकल्प खड़े हुए हैं, उनके बारे में सोच-समझ कर फैसला किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि सदन इस संबंध में सरकार का समर्थन करेगा, हमारी नीतियों का समर्थन करेगा।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : अध्यक्ष महोदय, 13 दिसम्बर को हिन्दुस्तान की संसद पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, उससे हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर आघात पहुंचा है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से उसकी घोर निन्दा करता हूं।

जिन सुरक्षा-कर्मियों और वाच एंड वार्ड के लोगों ने अपने जीवन को हिंदुस्तान की संसद की गरिमा की रक्षा के लिए बलिदान किया, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मैं एक बात साफ-साफ कहना चाहता हूं कि जब आतंकवादी संसद भवन के अंदर पहुंच गये और सरकार की तरफ से बयान आता है कि सुरक्षा प्रबंध ठीक थे तो मेरा सरकार से पूछना है कि अगर सुरक्षा में कमियां नहीं होतीं तो हमारे सुरक्षा कर्मियों ने आतंकवादियों को गेट नम्बर एक पर क्यों नहीं रोका। इससे हमें जानकारी मिलती है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कमियां थीं। मैं इसके बारे में एक-दो बातें कहना चाहता हूं। इस समय संसद की जो सुरक्षा है उसको शीघ्र ही बढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, नॉर्थ-ब्लॉक, साउथ-ब्लॉक की सुरक्षा भी और सख्त होनी चाहिए। जो आतंकवादी हैं वे हमारे देश से बाहर के आतंकवादी हैं इसलिए

हिंदुस्तान की जनता को, आम जनता को और सब राजनैतिक दलों को मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए और इस विाय में ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिए।

12.23 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair.)

सदन में एक बात और आई कि जो आतंकवादी कैम्प देश से बाहर सक्रिय हैं उन पर लक्ष्मण रेखा पार करके आक्रमण करना चाहिए। इस पर हमारा सुझाव है कि सरकार को यह समझना होगा कि अगर पड़ौसी देश के साथ हमें बातचीत करनी पड़े तो हम करें और बाहर के जो देश हैं इस बारे में हमें उन्हें भी साथ लेना पड़ेगा जिससे उनकी भी राय हमारे देश के साथ रहे।

पोटो की चर्चा भी आ गयी जबकि इस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि पोटो के होते हुए भी संसद पर हमला हो गया। यह पोटो से नहीं रुक सकता है। हमारा सुझाव है कि हमें अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करना चाहिए और सुरक्षा कर्मियों को अच्छे हथियार देने चाहिए। तभी हमारे सुरक्षा-कर्मियों का मनोबल बढ़ सकता है।

हमारी पार्टी आरएसपी आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, उन कदमों का पूरा समर्थन करेगी।

इसके साथ मैं एक सुझाव देता हूं कि आपको अपोजीशन पार्टीज को कान्फीडेन्स में लेना चाहिए। इतना कहकर आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, वाच एंड वार्ड और दूसरी सुरक्षा एजेन्सियों के जिन कर्मचारियों ने 13 दिसम्बर को हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के पवित्र मन्दिर को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उन्हें मैं शिवसेना पक्ष की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें एक होकर लड़ना चाहिए। लेकिन कुछ भााणों को सुनकर मुझे दुख हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब डब्ल्यू.टी.सी. और पेंटागन पर हमला हुआ था तो अमरीका की सारी जनता और सीनेट अमरीका के साथ खड़ी हो गई और उन्होंने दहशतवादी विधेयक पारित किया। हमारे दो प्रधान मंत्री आदरणीय श्रीमति इन्दिरा गांधी और पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी मारे गये, उसके बाद भी इसका यहां विरोध क्यों हो रहा है, मुझे पता नहीं है । हमारे गृह मंत्री जी कोयम्बटूर में बाल-बाल बचे थे।â€¦(व्यवधान) Sir, there is some noise.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is a lot of noise. Shrimati Kailasho Devi, you are moving from one end to the other. Please sit at one place.

श्री मोहन रावले : माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा है कि लड़ाई अब अंतिम चरण में आ गई है। लेकिन आतंकवादियों की लड़ाई भी अब अंतिम चरण में आ गई है, तभी वे संसद भवन तक आ सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डब्ल्यू.टी.सी. पर वा 1993 में भी हमला हुआ था और वह हमला ओसामा बिन लादेन के निर्देश पर हुआ था। उसके बाद 2001 में डब्ल्यू.टी.सी. पर हमला हुआ। पहले हमले में कुल छ: लोग मारे गये थे, लेकिन अभी के हमले में पूरा पेंटागन और डब्ल्यू.टी.सी. ध्वस्त हो गये । मैं इसलिए सदन से प्रार्थना कर रहा हूं कि हम सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। लेकिन यहां बहुत मतभेद दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। गृह मंत्री जी ने जिस भााा का इस्तेमाल किया कि हमें आर-पार करना चाहिए, आर-पार का मतलब है सीमा पार। पाकिस्तान हमारे यहां आ चुका है, अब हमें सीमा पार करनी चाहिए और पाकिस्तान ऑकुपाइड कश्मीर में जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैम्प हैं, उन्हें डिमालिश करना चाहिए । अमरीका पर हमला होने के बाद उन्होंने तुंरत अपना रीएक्शन दिया, फिर हम ऐसा क्यों न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिवसेना प्रमुख श्री बालासाहेब ठाकरे की राय यहां रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलें। उसका सदन में विरोध हुआ था। लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि पाकिस्तान के लोग और आई.एस.आई. यहां आतंकवाद फैला रहे हैं और उसके जरिये हमारे निर्दोा लोगों को मार रहे हैं। इसलिए हमें उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी है। मुझे खुशी है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया। उसके बाद श्री बालासाहेब ठाकरे ने रमजान के दौरान हमले रोकने का विरोध किया था और शिवसेना पक्ष की तरफ से हमने यह बात संसद में रखी थी। हमें खुशी है कि बाद में माननीय प्रधान मंत्री जी ने वह बात स्वीकार कर ली। उसके बाद श्री बालासाहेब ठाकरे जी ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान देश में आतंकवाद चला रहा है, हमें उसके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इसका इसलिए विरोध किया था कि हम वार्ता के खिलाफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के जरिये हमारे जवानों और निरपराध लोगों को मार रहा है, इसलिए हम वार्ता का विरोध कर रहे थे।

हमारे प्रधान मंत्री वाजपेयी जी ने वह बात भी मान ली और शस्त्रबंदी खत्म कर दी। आज शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के बारे में सब लोग जानते हैं कि वे जो बात बोलते हैं, कुछ समय बाद वह बात सही निकलती है। इसलिए मेरी प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना है कि हम कितने दिन लाशें गिनते रहेंगे? आज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास आँकड़े हैं। आज पाकिस्तान बोलता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 47838 हमले के इंसीडेन्ट्स उन्होंने किये हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। उसमें 11241 सिविलियन मारे गए और 14000 टैररिस्ट मारे गए, 4035 सिक्यूरिटी पर्सनल मारे गए। आज मुशर्रफ हमसे सुबूत मांग रहा है - चोर मचाए शोर। क्या यह सुबूत नहीं है? हमारे पास आंकड़े हैं। उन्होंने आतंकवाद शुरू किया 1988 से। मेरे पास 1990 से आंकड़े हैं। 1990 में एक भी इंसीडेन्ट नहीं हुआ था। जो टोटल टैररिस्ट मारे गए वे 550 थे और उसमें एक भी विदेशी नहीं था। लेकिन 1997 के बाद 1075 आतंकवादी मारे गए, उसमें 250 विदेशी आतंकवादी थे। उसका परसेंटेज 24.2 बनता है। 1998 में 999 टैररिस्ट मारे गए और उसमें से 406 फॉरेन के टैररिस्ट थे। उसका परसेंटेज 40.6 था। 1999 में 1082 टैररिस्ट मारे गए। उसमें फॉरेन के टैररिस्ट थे 540 और 2000 में 1612 टैररिस्ट मारे गए और 870 टैररिस्ट फॉरेन के थे। इनका प्रतिशत था 53.9 प्रतिशत। 2001 में 1742 टैररिस्ट मारे गए, उसमें से 1032 फॉरेन के टैररिस्ट थे जिनका प्रतिशत 58.9 प्रतिशत है। आज वे हमसे सुबूत मांग रहे हैं? सरकार के पास सुबूत हैं तो सरकार क्यों रुक रही है? सरकार क्यों नहीं कदम उठाती है? गृह मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूँगा कि कारगिल के समय हमने उनको जैसे सबक सिखाया था, वैसा सबक सिखाने की आवश्यकता है। सारा देश और सदन आपके साथ है। आप कदम उठाएं।

मुशर्रफ साहब हिन्दुस्तान आए थे। जब वे हिन्दुस्तान में आए तो उन्होंने कहा कि जो कश्मीर में आतंकवाद कर रहे हैं, वह स्वतंत्रता की लड़ाई है। जब वे यहां प्रधान मंत्री से वार्ता कर रहे थे तो हमारी सीमा पर गोलीबारी हुई और 17 जवान मारे गए। यह कहाँ का न्याय है? पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और हमारे पास इसके सुबूत हैं। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि आई.एस.आई. के जरिये लश्करे-तइबा और जैशे-मोहम्मद ने हमला किया है। हमारे पास सुबूत हैं। पाकिस्तान को लगता है कि हम जो आतंकवाद कर रहे हैं, हमारी भूमि पर कर रहे हैं, हमारे जवान मारे जा रहे हैं। आज मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हुर्रियत कॉनफ्रेन्स के जिलानी के बयान की जांच कीजिए। उन्होंने 8 दिसंबर को प्रेस कॉनफ्रेन्स की थी और कहा था कि 12 या 13 दिसंबर को हिन्दुस्तान में क्या होता है देखते रहना। आप उसकी जांच कीजिए। आज जो शौकत पकड़ा गया है, जो मोहम्मद â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude now. There are a lot of Members to speak.

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अमेरिका की बात करना चाहता हूँ। अमेरिका पर ओसामा बिन लादेन ने 1993 में हमला किया था। उसने एक इस्लामिक

जेहाद की पुकार की थी।

उपाध्यक्ष महोदय, ओसामा बिन लादेन ने इस्लामिक जहर फैलाने का काम किया। उसके बाद 1994 में बिल क्लिंटन फिलीपाइन्स गए थे, तो उनके ऊपर हमला हुआ, अमेरिका की फौजें सोमालिया से जब वापस आते समय एक होटल में ठहरीं तो उसके ऊपर हमला किया गया, कीनिया और तंजानिया में अमरीकियों के ऊपर हमला हुआ। इसलिए अमरीका को पता था कि ओसामा बिन लादेन अमरीका के ऊपर हमला कर सकता है। उसने 1998 में घोषणा की थी कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं, हर अमेरिकी हमारा दुश्मन है और इस प्रकार से उसने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी और 11 सितम्बर को हमला किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ। उसके लिए सुरक्षा कर्मियों को दोष देना ठीक नहीं है। आतंकवादियों को ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी कैंपों में प्रशिक्षण दिया, उन्हें हथियार और पैसा दिया। जब संसद भवन पर हमला हुआ, उस समय गाजी बाबा पाकिस्तान में था, लेकिन जो मुख्य कलप्रिट मोहम्मद था, उसने फोन कर गिलानी से पूछा था कि संसद में कितने सांसद और मंत्री मौजूद हैं, फोन पर हमें बताओ, लेकिन पता नहीं किन कारणों से गिलानी ने फोन नहीं किया और आतंकवादियों ने संसद में प्रवेश कर लिया। यदि उसने फोन किया होता और आतंकवादी संसद भवन में घुसने में कामयाब हो जाते, तो भगवान ही जाने कितना भयावह हादसा होता, लेकिन वह टल गया। मैं कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई किसी एक की नहीं है, बल्कि सारे सदन और सारे देश को मिलकर लड़ना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के इस्लाम धर्म के प्रमुख शाही इमाम और उनका लड़का खुलेआम कहते हैं कि हम तो आई.एस.आई. के एजेंट हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। उसके लड़के ने कहा कि आई.एस.आई. या पाक आतंकवादी जो लड़ाई कश्मीर में कर रहे हैं, उस पर उन्हें नाज है, गर्व है, लेकिन खेद की बात है कि हमारी सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। हम आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमारी सरकार देश के इस्लाम धर्म प्रमुख के सरासर देश विरोधी बयानों के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करती।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां मुलायम सिंह जी नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अखिलेश जी तथा अन्य नेता बैठे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं और हमारी पार्टी शिव सेना, किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, हम उनके खिलाफ हैं, हम आई.एस.आई. के खिलाफ हैं। यदि ऐसी बात नहीं होती, तो जब इस देश की संसद पर हमला हुआ तो क्यों नहीं इमाम बुखारी और देश के अन्य मुस्लिम नेताओं ने एकजुट होकर, एक मंच पर खड़े होकर इस आतंकवादी कार्रवाई का विरोध किया। जब अमरीका में 11 सितम्बर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और 13 दिसंबर को भारत की संसद पर आतंकवादी हमला हुआ, तो क्यों नहीं एक आवाज में उन्होंने इसका विरोध किया ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में यह स्पट कहना चाहता हूं कि हमारी शिव सेना पार्टी बंगालियों के विरुद्ध नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि बंगलादेश से जो लोग भारत आए हैं, वे बंगलादेश वापस जाने चाहिए। पता नहीं सोमनाथ चटर्जी हम पर क्यों नाराज हो जाते हैं। हमने कभी बंगालियों का विरोध नहीं किया। हम चाहते हैं कि आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश आदि जो सात पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें बंगला देश से आए लोगों को वापस भेजा जाए। वहां पाकिस्तान समर्थित आई.एस.आई. द्वारा जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे समाप्त करना चाहिए। हमारी मांग है कि बंगला देश से आए लोगों को बंगला देश वापस भेजा जाना चाहिए। इसमें वोटों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम बंगलादेश के लोगों के खिलाफ हैं, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए और सोमनाथ जी की पार्टी के लोग यहां बैठे हैं, वे मुझे बताएं कि मैं क्या कोई गलत बात कह रहा हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि बहुत सफाई हो गई, आपकी और आपकी पार्टी की बात को पूरी तरह हम समझते हैं। अब कृपया समाप्त करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मोहन रावले जी, अब आप समाप्त करिए।

श्री मोहन रावले : आई.एस.आई. के माध्यम से पाकिस्तान हमारे देश में जहर फैलाने का काम कर रहा है। कल हमारे नेता प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा ने जो पोटो और मदरसों के बारे में कहा था कि अगर पाकिस्तान मदरसों के माध्यम से आतंकवाद की शिक्षा देता है, तो उन्हें बन्द करना चाहिए। जिस प्रकार से अमरीका ने कानून पारित किया है और जैसा पांडियन जी बता रहे थे कि अगर हम पोटो विधेयक को पास कर देते, तो शायद ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरी विपक्ष से प्रार्थना है कि हम आतंकवाद से लड़ने के लिए खड़े हैं और हमें आतंकवाद से लड़ना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मोहन रावले जी, बस, अब एक वाक्य में समाप्त करिए।

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में अपना भाषण समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

SHRI VAIKO (SIVAKASI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I extend my thanks to you for having given me this opportunity to participate in the most significant debate of Lok Sabha in recent years.

Sir, 13th December will go down in the annals of the history of parliamentary democracy as a day of stupendous supreme sacrifice of our security personnel and members of the parliamentary staff.

The hon. Prime Minister very aptly stated that with a deliberate design and plan, the ISI of Pakistan engineered this atrocious and audacious assault on Parliament of India, using the terrorist outfits of LeT and JeM. The terrorists with a deliberate design might have planned to storm the gates using AK-47 rifles and grenades by claiming the lives of the security personnel there and to enter the inner gates of Parliament, to achieve their treacherous and nefarious ends.

I shudder to imagine what would have happened had both the Houses of Parliament on that day not adjourned, had the hon. Prime Minister been present in the Rajya Sabha as usual on that day during Question Hour, and had the terrorists entered the Upper House. I shudder to imagine what would have happened had the terrorists − especially the suicide bomber, Mohammad − entered the Central Hall where all the Opposition leaders and other Members of Parliament usually gather. I shudder to imagine further as to what would have happened, because a tragedy of monumental proportion would have occurred which would have resulted in a devastating consequence, paralysing the whole country. That was thwarted and prevented by the security personnel and Watch and Ward staff of

Parliament; otherwise, the terrorists would have put their own feet and stepped inside Parliament. Braving the bullets and getting injured, at the same time, without getting panicky, not only the security personnel but also the members of the staff who were not armed, were trying to protect the Members of Parliament.

They did their patriotic duty. Shri Matbar Singh received bullet injuries; and with that, he bolted Gate No. 11, thereby preventing the terrorists from gaining entry into Parliament House. I salute their bravery and I salute their patriotic courage and dedication.

With all pain and anguish my heart goes out to the bereaved members of those families. Our condolences or homage would not erase the tears of the mothers, widows and their orphaned children. But in this mortal world, they will live as immortals. The flame of the supreme sacrifices of those martyrs will glow for years in the hearts and minds of the people.

We may recall the attack on the twin towers of WTC on 11th of September. The whole world was stunned to see the totally destroyed twin towers. Within 45 to 60 minutes the terrorists were able to attack Pentagon, the most powerful military headquarters of the United States of America. Even then there was not an iota of whisper or murmur from any quarter, either from media or from any Opposition Party. We may say that to search the culprit it has gone all over the world, particularly beyond the borders of Pakistan.

We are a vibrant democracy. Even on 13th December, till five minutes past eleven of the clock we could hear acrimony or wordy quarrels inside the House. But if the Pakistanis had thought that they would create some dissent in the country, I think they are living in a fool's paradise. In contrast, what happened when the challenge was thrown; when the enemy, the Pakistani nationals, threw gauntlet at the gates of the Parliament? We all, forgetting our differences, stood as one nation. This is the message that should go from this august House to Pakistan. Whenever there is a grave challenge, in this case the bugle of confrontation was blown by the enemy at the gates of the Parliament, people belonging to different religions − Christian, Muslim, Hindu, Sikh, Jain, Buddhist − have stood as one to protect the unity of the country. This is the message that should go to Pakistan.

During our deliberations yesterday, a point was raised that we could cross the Line of Control. It was discussed in the electronic media also. It is the right of a sovereign country to defend itself. In the case of United States of America, when its right was violated, it extended its action up to Kabul, Kandahar and Tora Bora Hills in Afghanistan. India also has that right. We cannot forget history. During the days of John Kennedy when the crisis of Bay of Pigs was there, the United States of America had the audacity to tell the whole world that they would waylay the Soviet ships in the Atlantic Ocean and would target the bases of Cuba, another sovereign country, risking another war of catastrophe and nuclear destruction.

Therefore, could we cross the Line of Control? We have restrained. We have fought four wars. In the year 1947, we could have chased them; we could have occupied the whole territory; and we could have occupied the Pakistan-occupied-Kashmir also.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI VAIKO : Sir, I will take four to five minutes more.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have already taken much time.

SHRI VAIKO : Sir, it is a very important discussion. This is not for any party politics. It is an important and a significant discussion. I am not a person who speaks on every debate. When I feel to speak on important issues, I have to speak. Sir, kindly permit me.

Sir, we have restrained ourselves, in 1965 war when Lal Bahadur Shastri was there. We had restrained again in the year 1971 during Bangladesh war. We had the magnanimity when they surrendered. Nearly 100,000 prisoners of war were there. We had shown restraint during the Kargil conflict. We could have targeted and attacked them. We could have crossed the Line of Control. But we had restrained ourselves. But, Sir, what action should be taken? Appropriate action will be taken by this Government at the appropriate time. We had given a befitting reply during Kargil war.

Today, Mr. Pervez Musharraf is a prisoner of military people and ISI which is his own creation. Sir, there are two voices from Pakistan. One voice comes from its Foreign Office, and a contradicting voice comes from military spokesman. Therefore, most of the years, Pakistan has been under the spell of military dictatorship. They would try to have any misadventure but today the message is very clear. When there is a crisis, this country will rise as one nation, and proper lesson will be taught to the enemy at the appropriate time. Therefore, I am happy and proud about our Indian Parliament and the political parties. At this moment, everybody has forgotten the differences. Of course, one or two statements were there about blunders and monumental lapses. But let us forget those things. Yesterday and today, what we heard is the voice of Parliament, and this is the voice of the Indian Parliament to the world.

Sir, today, when Taliban are on the run, I apprehend running Taliban joining hands with the terrorists of these outfits. They could be hand-in-glove with the ISI and try to send their agents for provocation inside India. They will try to target not only Parliament but also the other important places throughout India.

Sir, a great challenge is there. But the eternal vigil is there. That is the need of the hour. We extend all our solidarity and support to the Government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee. He has stated that a decisive phase has come. We have a battle which has reached a decisive phase. The hon. Home Minister should spell out a resolution and have it adopted by the Cabinet that we will liquidate terrorists wherever they are and whoever they are. Let us stand unitedly by the side of the Government. In the hour of crisis, the same spirit which is being witnessed today and yesterday, should be continued. This is my appeal to all sections and all the political parties.

SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the very outset, I would like to pay my respectful homage to the memory of those friends, those security personnel and those who have made the supreme sacrifice to save the lives of us all. They have saved the lives of the hon. Speaker, hon. Deputy-Speakers, hon. Ministers, hon. Members of both the Houses of Parliament and the lives of the officials of this august body. They have not only saved the lives of these people, but also the dignity and the prestige of this highest institution of democracy of this country. At this moment, with my full voice, I condemn the attack of terrorists on Parliament.

Even after all these discussions, one thing cannot be denied that there were some security lapses. How the terrorists could come to the inner premises of the Parliament House itself remains a question mark. Even so, this is a critical juncture and at this critical juncture, definitely Members of both the Houses and the people of the country at large should be united. There is no doubt about it.

At the same time, I would like to know whether this unity is possible by dividing the country on the lines of caste and creed. I would like to make it very clear that it is not possible. On the one hand the NDA partners have been giving slogans like let there be Ram Janambhoomi Movement, the temple should be built by 12th March 2002, etc., and on the other hand the Government says let us be united. Some of them are saying that only Muslims are responsible for all this and some others are saying let us be united. How is this possible? All are patriots. Patriot is a Hindu, a Muslim and a Christian and all of them should be united at this critical juncture.

There have been some security lapses; we cannot deny it. After what happened very much the same way in the Jammu and Kashmir Assembly building, the Government should have taken some measures. Moreover, there have been news-items by a number of media sources that Parliament may be attacked. Therefore, I would like to know from the hon. Home Minister as to what measures he has taken after receiving all this information. I feel there has been some messing up of the intelligence collection. If so, what are the reasons for this and what measures have been taken by the Government so that such an incident does not recur in future?

I do not want to comment on the patriotism of the hon. Home Minister; nor that of the hon. Prime Minister. Definitely they are nationalists. Even then they may have to clarify this not just to us, but to the countrymen in general as to why this has so happened.

There has been an opinion expressed and a hue and cry raised in the NDA quarters and outside also that let there be a war if − of course they have mentioned it − war is the only alternative. I think, if we have to fight terrorists, we must have to go through the history of terrorism, particularly its recent history. Who is Osama Bin Laden? Can we forget the role of the United States of America?

13.00 hrs.

Osama Bin Laden has been designated as a terrorist throughout the world. It is the creation of USA. You cannot deny that. If it is so, we should not be guided by whatever USA may say today. Mr. Home Minister, through you, I would like to warn the Government. Do not take the so-called assurance, the so-called suggestion and advice of the USA in this manner. What role did they play in Pakistan and what role they are playing in India? We should study all these things since 11th September till today. It is easy to say anything. Ultimately, it will not be just a war or shellings or anything else but it will be a nuclear war because both Pakistan and India possess nuclear weapons. If it is so, we must be cautious of it. Before that, through you and the Home Minister, I would like to put a question to the hon. Prime Minister.

13.01 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

It is stated and admitted that the hon. Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee is a very nice diplomat and a good statesman. I would like to know very clearly from the hon. Prime Minister whether he has exploited and exhausted all options of diplomacy not only regarding this crisis but also of the relationship between India and Pakistan. If it is so, please let us know about it. The country should know what diplomatic relations you have made so far and what diplomatic channels you have got so far. At this critical juncture, I would like to know whether you are going in the right path. Definitely, we are patriots and I have personally fought for Independence. Today also, we are for India's Independence and unity. I would like to share my views along with you and I support all your causes if they are in the right path.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU (TENALI): Mr. Chairman Sir, the brutal attack that took place on the Indian Parliament on 13th December, 2001 is an attack not merely on the very structure of Parliament but on the whole Indian democracy and the sentiments of every Indian was wounded by the terrorists. With this incident, the patriotic spirit of every citizen has now been roused. We have been looking at the spirit and tenor of all the speeches of the political leaders since yesterday. In one voice, everybody is telling that India is one and Indians are united.

In times of crisis, India will not hesitate to unitedly curb this terrorism and show these conspirators, abettors and promoters, who are from Pakistan, their place. The statement made yesterday by the hon. Home Minister has categorically mentioned that this terrorism has been supported and promoted by Pakistan by extending support to terrorist outfits like *Laskhar-e-Toiba* and *Jaish-e-Mohammad.* Pakistan cannot escape from the evils of its own actions. If not today or tomorrow, it has to pay a price for promoting this kind of terrorism on some day.

We must congratulate the hon. Prime Minister, the Home Minister and the Government of India on having taken the ready initiative in nabbing these conspirators, on arresting the people who are abetting this conspiracy, and on securing the technical clues as to why and how this terrorist activity has taken place. Necessary proof and evidence have also been sent to Pakistan. This is really a feather in the cap of the Government of India as it has taken the steps immediately. Here, everyone of our leaders and others who spoke have paid encomiums for the supreme sacrifice that has been made by our security forces on the day of the incident, that is 13th December, 2001. They, very boldly, obstructed the terrorists from entering inside Parliament. It is their timely action which had averted the major catastrophe in this country. As such, everyone of the security forces need to be congratulated on having risen to the occasion. We must also salute the security persons who have laid down their lives in the hour of crisis.

The moment our Chief Minister came to know of this incident in Hyderabad, he had immediately called on the phone the hon. Prime Minister, hon. Speaker and other senior leaders of this country and expressed solidarity of the Telugu Desam Party. He had categorically stated that the Party would be with the Government in every action and decision that it takes. The security forces by averting this major catastrophe have lived up to the expectations.

Sir, whatever assistance given to the families in the name of ex-gratia should be increased to the extent of Rs. 50 lakhs. Even this cannot compensate the loss of lives. But they deserve this and this has to be increased to this extent.

While the incident took place between 11.40 a.m. and 12.20 p.m., immediately, the hon. Prime Minister and the other senior leaders visited the place of that incident. Even when the incident had happened in the U.S.A. on 11th September, Mr. Bush did not act so immediately. But our hon. Prime Minister acted immediately to inculcate confidence in the security forces....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : Sir, in this type of a discussion, let us not be just going on giving the warning bell. I think let it take a few more hours. What is there? ...(*Interruptions*)

SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): We are supporting it. Let him speak. What is wrong in that?

I think the hon. Home Minister will agree that since this matter has got a larger proportion, he would agree to our request to extend the time of this discussion because many hon. Members, sitting either on this side or that side, are eager to participate in the discussion. Why should he scuttle this? We know that the hon. Home Minister is going to give his reply around Two of the Clock. But let us extend the time by another two hours. What is wrong in that? Let us agree to that suggestion so that more hon. Members can speak. Will the hon. Home Minister agree to this suggestion?...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): There is no objection from my side. It is in the hands of the Chair....(*Interruptions*)

SHRI S. BANGARAPPA : Let it continue for the whole day. What is wrong in it?...(*Interruptions*)

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : At least, in this discussion, let opinions be expressed freely from all the quarters so that it will be helpful to the Government also.

Coming to my point, I would like to say that when the incident took place, several apprehensions have also come out saying whether there are any failures of the intelligence network, whether there are any failures of the security forces, and whether the Government has shared the information or not. All these things have come up. All these things are only mere suggestions to plan for the future.

When the Jammu and Kashmir Assembly was attacked, immediately there were messages saying that several democratic institutions in this country are going to be attacked. The hon. Speaker in the Parliament has also constituted a Committee to review the whole security of Parliament House. The Committee has given its report. The Committee has also made certain recommendations. I think, the hon. Speaker has also accepted all the recommendations. The security of Parliament House is also going to be beefed up. Under the Chairmanship of the hon. Deputy-Speaker, the Budget Committee of Parliament has also met and made additional allocations to meet the expenditure of the additional security forces. So, as far as providing security is concerned, there are no two opinions about it. Everybody is one. There is no doubt about it. The security of this House and the Indian democracy and Indian Parliament is supreme. The Government of India is also coming forward to do it....(*Interruptions*)

Here, we must make a mention about the media persons also. In spite of this type of terrorism that was prevailing at that point of time, the media people, particularly the photographers and videographers, had been trying to capture the scenes of terrorism without any fear. Really, it would provide the total information about what had happened. In the process, they did not even hesitate to risk their lives. Several people had got injured. All that must be appreciated for their act of bravery at that point of time.

The hon. Prime Minister really deserves to be congratulated for having roused the morale of the people in Parliament House. This is a time when every Indian has to come together....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Time allotted to each party is limited.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You have already taken 15 minutes.

...(*Interruptions*)

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : Sir, I would take another four or five minutes. ...(*Interruptions*)

The militancy and the domestic terrorism which were prevailing all these days have taken very costly lives in this country, right from Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi and the Chief Minister of Punjab. The extreme activity of militancy and other activities took all these lives. Added to this, cross-border terrorism and international terrorism have posed a different type of threat to attack all the democratic institutions and strategic institutions across the globe. This is where we have to unitedly condemn the activities of these terrorists and also condemn the activities of the promoters, negotiators, abettors and conspirators of these terrorist activities.

I do not know as to how Pakistan has come up with a new theory of a joint probe when it is pampering the terrorists and when it is responsible for these types of activities. It is now advocating that a joint probe is to be instituted. I do not know as to what exactly is meant by joint probe when we are the people who suffered at this and when Pakistan is promoting these types of activities. How is it possible? This has to be summarily rejected. This is not to be accepted and we cannot pledge our sovereignty by accepting a joint probe with Pakistan.

Yesterday, after hearing the spirit of the speeches of the leaders in this august House, yesterday even the United States of America has said that it is concerning the sentiment of the country and whatever action that the Government of India is going to take in self-defence, it is going to be one with them.

Lastly, we may have to take certain steps in regard to the security arrangements prevailing here by watching some of these events that have been taking place against these institutions. The Parliament House should have closed circuit televisions not only inside the building but also all around the building so that the total movements can also be videographed and the same is kept for records. The Telugu Desam Party feels that there is need for earlier solution with regard to the issue of Pakistan-sponsored terrorism, organising training camps and the evil plans that are being hatched.

Even for entering into Pakistan-occupied-Kashmir, as the hon. Prime Minister has very rightly said, we have to take very balanced and correct steps, at the correct time. We have the greatest confidence in this Government and in the hon. Prime Minister that the Government would certainly take a correct step and a correct decision at the right time. It has been evidently proved at the time of Kargil war when we were very successful.

Sir, we are quite confident that we would be able to face terrorism and India will be one in this regard. The Telugu Desam Party will support the decisions and actions that are going to be taken by the Government from time to time in this respect and POTO is one such thing in this context. So, in the light of the recent events, POTO also has to be supported by all the parties.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me a chance to participate in this debate. At the very outset, I pay my tributes and homage to the martyrs who have laid down their lives to protect this Parliament building, hon. Members of Parliament, Ministers, staff and others who were present in the building at the time of the terrorist attack.

Sir, in his statement, the hon. Home Minister said that this terrorist assault on the very bastion of our democracy was clearly aimed at wiping out the country's top political leadership. He said it very rightly. So, we condemn this attack and my party also condemns this attack.

Today, I listened to the speech of the hon. Prime Minister very carefully and I appreciate him for that. The fight against terrorism is a must. Terrorism cannot be tolerated. No civilized country can tolerate terrorism. The urgency of the unity of all the political parties and the urgency of the unity of the people of our country is a must. The whole country is united in its fight against terrorism and there is none to dispute it in this august House. All the political parties of different shades are united in order to fight the menace of terrorism. But, in this context, the people of our country have got every right to know about the performance of the Government. It is known to us and it is known to everybody that before the 13th December, our hon. Prime Minister and Home Minister had declared publicly that Parliament is under threat of attack by terrorists. They had some prior information. So, we would like to know from the Government as to what steps they have taken before the 13th December, to counter the threat of terrorist attack, as they had got adequate information from intelligence agencies, Mumbai Police and other sources.

Sir, today also, the hon. Prime Minister had admitted that there was a security lapse. Even the Minister of State for External Affairs, Shri Omar Abdullah said that yesterday, but this is not enough. In each and every case, the Government invariably says that there was a security lapse. We cannot forget the assassination of our former hon. Member, Shrimati Phoolan Devi, which happened during the Monsoon Session of Parliament.

We cannot forget the strike on the Red Fort. We cannot forget the attack on pilgrims to Amarnath. So many events have been there. In each and every case, our Government is playing one record that a lapse in security was there. Is it a proper reply? Are they serious in taking the expectations of the people? They are asking the people to be united. But what are they doing? So, only the lapses in security are not sufficient. The country has every right to know why such a lapse was there as they had adequate information before hand.

I am not going to cover more and more points. But I must say something in a positive manner. I shall make some positive approach before the Government. Yesterday, I listened to the speech of the Minister of State, Shri Omar Abdullah. I must say that he could not satisfy me. He is the Minister of State in the Ministry of External Affairs. What is he doing about the diplomatic initiatives? What steps has he taken? In this respect, our Government should come forward to mobilise the world opinion. I am not dealing with whether Parliaments of different countries have sent their messages here. This is not the point. The point is that almost all the countries sent their messages. They have extended their support. This is enough. We should try to mobilise them.

What about the UNO? I would like to know whether the Government is making any contacts with the UNO. Some hon. Members of this august House referred to the USA. They referred to the happenings of 11th September in New York. Do we want to fight terrorism on the lines of the USA? Do you think that Mr. Bush in the USA or Mr. Tony Blair would be mentors of our country? I agree with the Prime Minister that we would fight terrorism in our own style. We must fight terrorism in our own way. The 'own way' is to mobilise the world opinion. 'Our own way' is to mobilise all the people of this country. The 'own way' is to take the House into confidence. The 'own way' is to take all the political parties into confidence. This should be done. The terrorist outfits are supposed to be comprising the Muslims.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI PRABODH PANDA : Sir, I am a new Member. Please allow me to speak for some time here.

It is seen that the USA is continuing its fight against Osama bin Laden. They are continuing their fight against the Talibans. Not a single Islamic country has opposed it. Not a single Islamic country has supported Osama bin Laden. Why is not our Government willing to mobilise all the Islamic countries so that they could pressurise and restrain Pakistan? I think, they should do it.

Lastly, I must say that this might be a long − not the last − occurrence that has taken place here. In the coming days, there may be so many happenings. I hope that, at least, next time the Government will not play such a record that only a lapse in security was there.

Security is the most important thing. We must have tight security in all respects, particularly in the places of the sensitive areas.

Mr. Chairman, Sir, as you are not allowing me to speak more, I conclude my speech and I thank you very much for giving me this opportunity to speak.

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : सभापति महोदय, 13 दिसम्बर के दिन संसद पर जो आतंकवादियों का आत्मघाती हमला हुआ, वह हमारे देश के प्रेम, प्यार और भाइचारे को बिगाड़ने का एक प्रयास था, हमारे देश की एकता और अखंडता को बिगाड़ने का प्रयास था। हमारी पार्टी उस हमले की घोर निन्दा और भर्त्सना करती है और सुरक्षा बलों के उन जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देती है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए, संसद को बचाने में अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने लोकतंत्र और इस देश की एकता और अखंडता को बचाने में अहम भूमिका निभाई। हम उन सुरक्षाकर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उन बहादुर वीरों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं और भविय में भी नहीं कहा जा सकता कि वे नहीं होंगी, चाहे जम्मू कश्मीर विधान सभा का क्षेत्र हो, चाहे सबसे बड़े लोकतंत्र का क्षेत्र संसद भवन हो। ऐसे लोग अपना आतंक फैलाने के लिए हादसे करते रहते हैं। लेकिन हमारे सुरक्षाकर्मियों, हमारे देश के नेताओं और जनता का यह फर्ज बनता है कि वे इस बात का मुद्दा भी रखें कि उन हादसों में कम से कम नुकसान हो, कम से कम जान-माल की हानि हो। अपने आपको समृद्धिशाली और बलशाली कहलाने वाला देश अमरीका, जिसकी खुफिया एजैंसीज़ के बारे में माना जाता है कि वे पूरे संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, वह भी पैंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सैंटर पर हुए हमले को रोक नहीं पाया। हमारे सुरक्षाकर्मियों ने बचाव करके जो कम से कम नुकसान होने दिया, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। अगर हम पहले के हादसों को देखें तो हमें कहीं-कहीं कमियां लगीं। अब हमें देश के खुफिया तंत्र, खुफिया एजैंसियों की सतर्कता को बढ़ाया जाना चाहिए। हमें जो खबरें मिलती हैं, वे वक्त पर और सही मिलें, हमें ऐसे प्रबंध करने चाहिए। अगर खुफिया तंत्र में कहीं लचीलापन है तो पूरे ढांचे को नए सिरे से सुदृढ़ करके प्रभावशाली कदम उठाए जाने चाहिए।

प्रतिपक्ष और पक्ष के नेता और प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आज भी अपने भााण में कहा कि हमने बहुत संयम बरता है और यह हकीकत है कि अहिंसा के पुजारी देश, महात्मा गांधी के आदर्शवादी देश ने बहुत संयम बरता है। जो देश हमें इस बात की सलाह दे रहे हैं कि संयम बरतना चाहिए, उनसे हम कहना चाहते हैं कि सब्र की भी सीमा होती है, सब्र के बांध तोड़े नहीं जाते, वे अपने आप टूट जाते हैं और उनसे जो प्रतिक्रिया पैदा होती है, उससे अपने आप समाधान निकल आता है। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमें आर-पार की लड़ाई लड़नी है, निर्णायक लड़ाई लड़नी है। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आज आर-पार की लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है और इसे हमारे पड़ोसी देश, चाहे पाकिस्तान है या कोई और, यह नहीं समझें कि उनके वजूद को खतरा है।

इससे आतंकवादी यह समझें कि उनके वजूद को खतरा है, उस धरती को खतरा है, जहां आतंकवादी पैदा होते हैं, उस धरती को खतरा है, जहां आतंकवाद पलता और बढ़ता है। हम लड़ाई के पक्षधर नहीं हैं, युद्ध के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन वक्त आने पर हमारे देश के हित के लिए और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमें हथियार भी उठाने पड़ें तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी सीमाओं के बचाव के लिए इस देश का एक-एक नागरिक बहादुरी से लड़ने के लिए तैयार है। आज जनभावना है कि आतंकवाद को जड़ मूल से खत्म करना है। हमारे देश का अगर इतिहास उठाकर देखें तो यह चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञों का भी देश रहा है। आज हमें राजनैतिक कूटनीति भी खेलनी है। अगर हम शिवाजी महाराज को याद करें तो छोटी सी सेना के साथ अपनी कूटनीति से छापामार युद्ध प्रणाली को तैयार करके उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। हम अपनी कूटनीति से हमारे दुश्मनों को यह दिखा सकते हैं कि हम किसी भी चीज में कम नहीं हैं।

हमें अपनी सीमाओं को भी मजबूत करना है। आज जो आतंकवादी हमारी सीमाओं के घेरे में आ जाता है, उसमें मेरा एक सुझाव है कि निर्जन पट्टी अगर हम हमारी सीमाओं पर 10-15 किलोमीटर की बना दें, जहां हर वक्त हमारी सेनाओं का पहरा रहे, आतंकवादी उसमें घुसने की हिम्मत न कर सकें तो मैं समझता हूं कि हमें आतंकवाद को रोकने में बहुत मदद मिलेगी।

आखिर में, आपकी घंटी बजे, उससे पहले मैं कहूंगा कि एक कहावत है कि गरजने वाले बरसा नहीं करते। हमारे बड़े-बड़े नेताओं के बयानों के बारे में जब आम जनभावना यह आती है कि गरजने वाले बरसा नहीं करते, तो आज हमें यह भी सिद्ध करना है कि जब गरजने वाले बरसने पर आ जायें तो तूफान आ जाते हैं और इस तूफान में हमें यह प्रण करना होगा कि आतंकवाद को जड़ मूल से बहाकर हमें नट करना है, यही हम सब को प्रण करना है।

आपने घंटी नहीं बजाई, इसके लिए आपके बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : सूची आम तौर से समाप्त है। मध्यावकाश के बाद सरकार का उत्तर होगा।

14.43 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

TERRORIST ATTACK ON PARLIAMENT HOUSE – contd.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, रामदास आठवले जी के बिना पूरी कार्यवाही अधूरी रहेगी। इन्हें दो मिनट अपनी बात कहने का मौका दे दें।

MR. SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, two minutes, please.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, संसद पर जो हमला हुआ है, उसका हम प्रतिकार करते हैं। जिन लोगों ने हम सभी को बचाने का प्रयत्न किया और अपना बलिदान दिया, उन पर गर्व करते हुए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अटल जी आप कब लड़ोगे आर-पार की लड़ाई,

आप तो मार रहे हैं खाली-पीली बड़ाई।

आप जल्दी से पाकिस्तान पर करो चढ़ाई,

नहीं तो हम करेंगे तुम्हारे साथ लड़ाई।

आतंकवादियों ने अपने देश की अस्मिता जिलाई है,

हम सबके एक रहने में ही देश की भलाई है।

हमारे लोकतंत्र की छवि उन्होंने मिट्टी में मिलाई है,

आपने अपनी सरकार काहे को चलाई है।

मंत्री जी देश को लूटो आपस में,

पोटो लाओ, तुम काम करो, पोटो।

और एक दूसरे को आपस में काटो

हमारे सत्ता में आने का पूरा करो मोटो।

फिर हम नहीं लाएंगे पोटो,

हम काम नहीं करेंगे खोटो।

यहां जो बात कही गई है कि हम सब लोगों को इस संकट की घड़ी में एक रहना है, यह सही बात है। आतंकवादियों ने जो भी काम किया है, उसका हमें कड़ा विरोध करना चाहिए।

चुनाव आएगा तब हम देखेंगे कि आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, तब हम हमारी भूमिका रखेंगे मगर आज हम सब लोगों को एक साथ आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है, पाकिस्तान को चेतावनी देने की आवश्यकता है। अगर मुशर्रफ यह चाहते होंगे कि पाकिस्तान के लोग हमारी पार्लियामेंट पर भेज दिये हैं तो हम लोग शांति का नारा देने वाले लोग जरूर हैं मगर वक्त आने पर आपके पाकिस्तान में जहां टैरेरिस्ट्स के कैम्प्स हैं, वहां हमें हमला करना होगा और उस हमले की प्लानिंग आप लोगों को करने की आवश्यकता है।

अमरीका में पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होने के बाद उन्होंने तालीबान पर दो महीने से जबर्दस्त हमला शुरू कर दिया है। आप भी अगर देश की चिंता करना चाहते हो तो आपको भी पाकिस्तान के साथ युद्ध करना होगा और युद्ध करने के लिए यदि आप तैयार नहीं हैं तो गद्दी छोड़ो। हम युद्ध का ऐलान कर देंगे। हम युद्ध का पूरा सपोर्ट करते हैं और आडवाणी साहब, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यहां के सब लोग आपके साथ हैं, आप एक्शन लीजिए। हम आपको ताकत देने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम एक्शन लेने का काम करेंगे। हम इस आतंकवाद की निंदा करते हैं। पूरा देश एक है। आप भी उधर एक हैं, हम भी इधर एक हैं। दोनों को मिलकर देश के लिए एक होने की आवश्यकता है। हमारी पार्टी की ओर से आपकी कामयाबी के लिए हम प्रार्थना करते हैं लेकिन अच्छा काम करने की आवश्यकता है नहीं तो जार्ज फर्नांडीज को बदलने का अब वक्त आया है और अब आडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी के भक्त बन गये हैं। इसीलिए हम उनका सपोर्ट करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

गृह मंत्री (श्री लाल कृण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, सचमुच में जब इस बहस में प्रधान मंत्री जी ने अपने विचार रखे और उससे तुरंत पूर्व विपक्ष की नेता ने अपने मत प्रकट किये तो मुझे लगता था कि यह ऐसा मौका था जब इस बहस को समाप्त करना चाहिए था क्योंकि एक प्रकार से जिस वक्तव्य के आधार पर यह बहस हुई और जिस वक्तव्य का अंतिम पैराग्राफ यह था:

> "The Prime Minister, in his address to the nation on the 13th December, 2001, has declared that the fight against terrorism has reached a decisive phase. The supreme sacrifice made by the security personnel who lost their lives in this 13th December incident will not be allowed to go in vain. Those behind the attack on Parliament House should know that the Indian people are united and determined to stamp out terrorism from the country."

यह अंतिम कड़ी उस वक्तव्य की है जिस पर यह सारी बहस चली है और मुझे लगता था कि प्रधान मंत्री जी के बयान से पूर्व विपक्ष की नेता का भााण और फिर उनका उत्तर, उसके बाद बहस पूरी हो गई और उससे यह जो संदेश है, जो इस अंतिम पैराग्राफ में है, वह संदेश देश को भी पहुंचेगा, विश्व को भी पहुंचेगा कि भारत र्वा के प्रतिनिधियों के नाते यहां की संसद ने यह निर्णय किया है कि हम आतंकवाद को कुचलकर ही दम लेंगे। इनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और इस दृटि से हम एकमुश्त हैं, यूनाईटेड हैं, कृत-संकल्प हैं और डिटर्मिन्ड हैं।

यह संदेश कुल मिलाकर, मैं मानता हूं कि कल और आज की बहस में से गया है।

चर्चा मुलायम सिंह जी ने शुरू की। आगे चलकर शिवराज पाटिल जी बोले और प्रायः मैं मानता हूं, जिन लोगों ने सरकार के किसी पहलू की आलोचना भी की होगी, तो उसका भी जो अंडरटोन था, वह सकारात्मक था। उसके जो भाव थे, उस भाव में यही बात थी कि आतंकवाद को समाप्त करना चाहिए। यह कृतसंकल्प है और साथ ही साथ यह भी था कि यह देश की एकता का अवसर है। उस संदर्भ में कुछ मित्रों ने यह बात भी कही कि जब हम एकता लाना चाहते हैं, तो कन्टेंशियस इशूज़ क्यों उठायें। लेकिन कन्टेंशियस इशूज़ उठे। हम न भी लाए होंगे, लेकिन कोई यहां से बोले और कोई वहां से बोले। ऐसे इशूज़ आए। इसलिए मैं मानता हूं कि जो दो बयान हुए हैं - एक हमारे सदन के नेता का और दूसरा सदन में विपक्ष के नेता का - उनसे एक प्रकार से जो संदेश हम इस प्रस्ताव के द्वारा या इस चर्चा के द्वारा देना चाहते थे, वह संदेश पहुंचा और सब को पहुंचा। सीमा के उस पार भी पहुंचा। मैं तो आज सुबह देखकर हैरान हुआ, जब मैंने हैडिंग देखा कि इस्लामाबाद के अनुसार मेरा वक्तव्य इन्फलेमेट्री था। मैं खोजने लगा और सोचने लगा कि मेरे किसी और बयान के बारे में कहा होगा । मैने दो दिन पहले टीवी पर भी कहा है, उस उनको आपत्ति हो सकती है, लेकिन कम से कम इस वक्तव्य में अगर किसी को आपत्ति हो सकती है, तो इस दसवें पैराग्राफ से पूर्व दो पैराग्राफ्स पर, जिनको प्रियरंजन दासमुंशी जी ने भी कोट किया है, उन पर हो सकती है। वह मेरा विश्लोण है। मेरा विश्लोण है कि पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक इस बात से रिकंसाइल नहीं कर पाया कि हमने तो टू-नेशन थ्योरी के आधार पर देश का विभाजन करवाया था। उस हिसाब से वह मुस्लिम देश बनना चाहिए था और यह हिन्दू देश बनाना चाहिए था, लेकिन यह सैक्युलर देश कैसे बन गया। आज भी भारत के लोग जब विदेश जाते हैं और लोगों को जब बताते हैं कि दुनिया के सारे इस्लाम देशों में से, इंडोनेशिया को छोड़कर, कोई दूसरा देश ऐसा नहीं है, जहां पर इतनी मुस्लिम जनसंख्या हो, जितनी भारत में है, तो लोगों को ताज्जुब होता है। इसीलिए मैं दोनों पहलू लाया। डैमोक्रेसी का भी लाया और सैक्युलरिज़्म का भी लाया। हम थियोक्रेसी को रिजैक्ट करते हैं, अथोरिटेरियन राज को रिजैक्ट करते हैं। इसलिए उनको लगता है कि ये सैक्युलर होते हुए भी, डैमोक्रेटिक होते हुए भी देश प्रगति करता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है तथा युनाइटेड है। उन्होंने जितनी लड़ाइयां हमारे साथ लड़ी है और आज भी जो लड़ रहा है, उसमें हमेशा यही बैकड्राप होता है कि यह देश एक नहीं रह सकता, विभाजित हो जाएगा। पहले तो पश्चिम के जो विचारक थे, पश्चिम के जो विद्वान थे, वे कहा करते थे कि नेहरु जी जब तक हैं, देख एक है.। नेहरु जी नहीं रहेंगे, तो लोकतन्त्र भी नहीं रहेगा और देश भी एक नहीं रहेगा। अनेक ग्रन्थ लिखे गए, लेकिन यह देश एक रहा है। अच्छा है, मुझे खुशी है, चाहे इस प्रसंग के कारण हो, जो 13 दिसम्बर को हुआ, निश्चित रूप से बहुत तकलीफदेह है, देश के लोकतन्त्र पर इस प्रकार हमला हो और उसमें हमारे इतने सुरक्षाकर्मी बलिदान हो जायें, निश्चित रूप से कटदायक तो है, लेकिन कटदायक होने पर अगर फिर से देश के इस एक स्वरूप को दुनिया के सामने रखा है, तो यह भी एक अच्छी बात है। स्वयं में अच्छी भी है, लेकिन स्वयं में यह घटना अच्छी नहीं है। लेकिन यह एकता जो आज और कल प्रकट हुई है, चर्चा में सभी सदस्य बोले हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं और पूरे सदन का अभिनंदन करता हूं।

अध्यक्ष जी, सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा है, संसद के इतिहास में यह एक सर्वाधिक महत्व की बहस है।

मुझे उनकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि उन्होंने बहुत ठीक कहा, It is a very important debate in the history of Parliament. Perhaps he said `the most important debate'. But something of that kind, उचित ही था। मैं स्मरण करता हूं जब आतंकवाद की, सुरक्षा की चर्चा होती है। व्यक्तिगत मेरे लिए शासन में यह दूसरा मौका है। आज से लगभग 25 साल पहले मोरारजी भाई की सरकार थी, तब की सुरक्षा की स्थिति और आज की सुरक्षा की स्थिति की मैं कभी-कभी तुलना करता हूं। मुझे आश्चर्य होता है और तकलीफ भी होती है। उन दिनों में सरकार के मंत्री के पास कुछ सुरक्षा नहीं थी। प्रधानमंत्री जी के पास भी एक-दो पीएसओ हुआ करते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी।

महोदय, मेरा जन्म कराची में हुआ। इन 50 सालों में मैं एक बार कराची गया हूं और वह उस काल में गया हूं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रहते उन्होंने मुझे निमंत्रणन् दिया था, तब मैं वहां गया था। वहां सैनिक राज था, जनरल जिया शासन कर रहे थे। चारों और सैनिक कर्मी दिखते थे, जहां देखो, चारों और आर्मी ही आर्मी दिखती थी। वहां के एमपीज़ और मिनिस्टर,पता नहीं कितनी सुरक्षा, व्यवस्था लेकर चलते थे, उसी बीच में मैं यहां से गया था। मैं कराची में अपने स्कूल में गया। अपने निवास स्थान पर गया। मैं वहां पर दो दिन रहा। लोग पूछते थे कि कौन हैं, हमारे पाकिस्तान के कर्मचारी और अधिकारी मेरे साथ थे, वे बताते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक केबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्हें ताज्जुब होता था कि इनके साथ कोई सिक्युरिटी नहीं होती, यह 1978 की बात है। आज मैं जहां जाता हूं, सारे ब्लैक केट कमांडो होते हैं, बहुत सुरक्षाकर्मी होते हैं। अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है।

इसलिए अगर कोई कहे कि पार्लियामेंट के बारे में चिन्ता नहीं हुई, आप पार्लियामेंट के बारे में कहते थे कि हमला हो सकता है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया तो मैं इतना ही कहूंगा कि चिन्ता नहीं हुई, यह कहना ठीक नहीं है। हम इसके प्रति उदासीन थे, यह कहना ठीक नहीं है। पाटिल जी ने इसका जिक्र किया, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने भी किया। इससे पहले भी चर्चा हुई है कि लोक सभा की सुरक्षा किस प्रकार से ठीक की जाए, इसके लिए कमेटी बनी है। स्पीकर साहब के निर्देशन में अक्तूबर के महीने में कमेटी बनी है। मेरे पास इसकी एक कॉपी है, इसकी पूरी रिपोर्ट स्पीकर साहब को दी है। यह दस अक्तूबर को बनी, जिसके अध्यक्ष सुरेश राय हैं - ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, न्यू दिल्ली रेंज, नई दिल्ली। उसमें यहां की सुरक्षा के कर्मी भी थे, महिपति, जो इस सारे के इंचार्ज हैं, वे भी इसके सदस्य थे। इस एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसे आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि प्रोफिटिक है। हमने जो कुछ 13 दिसम्बर को देखा, वह सब कुछ एक प्रकार से हो सकता है, यह-यह हो सकता है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। मैं उसे पढूंगा नहीं, क्योंकि वह सिक्रेट रिपोर्ट है। खास कर इसकी जो रिकोमेंडेशंस हैं, वे हमारे दुश्मनों के पास पहुंचे, यह मैं नहीं चाहूंगा। वैसे पार्लियामेंट का नियम है कि किसी भी दस्तावेज में से अगर कोई इसके बारे में कोट करता है, उसे कोई सदस्य मांगे तो उसे बताना पड़ेगा। उसे टेबल पर ले करना पड़ेगा, इसी कारण मैं नहीं कर रहा हूं, अन्यथा मैं आपको कह सकता हूं। इसे कोई पढ़ेगा तो समझ में आएगा कि सरकार उदासीन नहीं थी। स्पीकर साहब इसके बारे में चिन्तित थे और उन्होंने उस चिन्ता में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने कहा, आज जो व्यवस्था है वह सर्वथा अपर्याप्त है। उसमें ये-ये कदम उठाए जाने चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यह कहना कि प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि हमला हो सकता है, आडवाणी जी ने कहा कि हमला हो सकता है।

15.00 hrs.

यद्यपि जब मैंने हमले की बात कही थी तो जो व्यक्ति मुम्बई में अफरोज नाम का पकड़ा गया था उसके बयान के आधार पर कही थी। उसने कल भी कोर्ट में जाकर अपना बयान दिया है जोकि अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वह बयान वही है जो उसने पहले पुलिस के अधिकारियों को दिया है जिसमें उसने कहा कि 11 सितम्बर को डब्ल्यूटीओ और पैंटागन पर आक्रमण करने की जब योजना बनी थी, तभी यह भी योजना बनी थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स पर और भारतीय संसद पर हमला किया जाए। उस बयान के आधार पर जो जांच अब तक हुई है कि जो वह कह रहा है कि उसने फ्लाइंग की ट्रेनिंग आस्ट्रेलिया में ली, क्या यह सही है? जांच के बाद पता चला कि बात तो सही है। बाकी चीजें जो उसने कही हैं उनकी जांच हो रही है। उनके लिए आस्ट्रेलिया, यूके और अमरीका को भी

बताया गया था कि हम तो जांच कर रहे हैं आप भी जांच करो। भारतीय संसद पर भी हमला हो सकता है ऐसा उस व्यक्ति ने कहा है जो मुम्बई में पकड़ा गया है। यह बात मैंने इस संदर्भ में नहीं कही कि आत्मघाती दस्ते के पांच सदस्य यहां आकर हमला करेंगे। यद्यपि इस तरह के हमले का जिक्र इस सीक्रेट रिपोर्ट में है।

आज संसद में प्रवेश बहुत कठिन नहीं है। इतनी सफेद रंग की एम्बेस्डर कारें संसद में आती हैं और अगर उस पर कोई लाल-बत्ती लगा ले, वैब-साइट से डाउन-लोड करके झूठा स्टीकर लगा ले, होम-मिनिस्टरी का स्टीकर लगा ले तो कितने सुरक्षा-कर्मियों को हम उसके आधार पर डिस-मिस करने लगेंगे, और क्या हम इस तरह करके न्याय करेंगे। इसलिए जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है कुल मिला करके आज तक आतंकवाद के स्वरूप को पहचान करके जो भी समुचित व्यवस्था की जा सकती है वह हमने की है। मुझसे किसी ने पूछा कि कुल मिलाकर कितने सुरक्षा कर्मी संसद की सुरक्षा में हैं। मुझे बताया गया कि यहां पर संसद भवन के लिए सीआरपीएफ की सात कंपनियां हैं, दिल्ली पुलिस के 250 आदमी हैं, सीआरपीएफ महिला पुलिस की दो प्लाटून हैं। इसके अलावा सैक्रेट्री जनरल की तरफ से जो भी चिट्ठी आई, जितनी सुरक्षा की मांग उन्होंने की, भारत सरकार ने दी है, कभी कोई कमी नहीं हुई। हम जानते हैं कि संसद पर हमला बहुत बड़ी बात है और उसका विश्वभर में असर होगा। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि It is always easy to be wise after the event. हमने ये निर्णय पहले ही इम्प्लीमेंट कर लिये होते तो अच्छा होता। लेकिन आज की परिस्थिति में कुल मिलाकर जो तथ्य मेरे सामने हैं उनके आधार पर मैं सुरक्षा के बारे में शिकायत नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि सुरक्षा-कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया है और उनका तो हमें अभिनंदन करना चाहिए। अमरीका के सुरक्षा-कर्मियों के लिए 11 सितम्बर तकलीफ का दिन हो सकता है लेकिन 13 दिसम्बर भारत के सुरक्षा-कर्मियों के लिए एक गर्व का दिन है। उन्होंने बहुत बड़ी बात की है और हमें इस बात को पहचानना चाहिए कि terrorism through the agency of suicide squads एक ऐसा नया उपाय है जिसका कोई सरल हल नहीं है।

सलमान रूश्दी को जान का खतरा पैदा हुआ तो वह सालों-साल तक छुपे हुए बैठे रहे। किसी को पब्लिक अपीयरेंस नहीं देते थे और उसकी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार ने की। क्या हममें से किसी के लिए ऐसी व्यवस्था हो सकती है और क्या लोकतंत्र में यह उचित है? यह घटना होने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि आप यह विजिटर्स गैलरी में विजिटर्स का आना बंद कर दें। मैंने कहा कि ऐसा कैसे होगा, यह लोकतंत्र है।

मुझे एक बात का स्मरण है। जब बम विस्फोट बहुत होने लगे थे, उस समय एक बार कैजुअली सुझाव दिया गया था कि विजिटर्स गैलरी के चारों तरफ एक बुलेट प्रूफ कांच लगाया जाए लेकिन लोकतंत्र के अपने कुछ तकाजे हैं। कुछ ओपननैस चाहिए और वह जरूरी है। अलबत्ता मैं आज पाकिस्तान के रिएक्शन का जिक्र कर रहा था और वह रिएक्शन शायद इस पर हो सकता है। मैंने " टाइम्स ऑफ इंडिया" या कोई और अखबार देखा जिस में उन्हें शिकायत थी कि जैशे-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों पर दोष कैसे लगाया गया है?

> "Pakistan Foreign Minister, Mr. Abdul Sattar has rejected the charges made by Advani holding the two Pakistani based organisations, Jaish-e-Mohammad and Lashkar-e-Taiba responsible for the Parliament attack."

रिजैक्ट करने का कारण क्या है, उसके बारे में वह कहते हैं कि -

> "This is a prejudiced and biased allegation in order to defame the freedom struggle in Kashmir as terrorism."

अर्थात ये दो संस्थाएं हैं जो जम्मू-कश्मीर में अपनी गतिविधियां कर रही है और वे वहां फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है। उनके फ्रीडम स्ट्रगल को बदनाम करने के लिए इन संस्थाओं पर दोष लगाया है। मुझे स्मरण आता है कि आज से 5-6 महीने पहले जब प्रधान मंत्री जी के निमंत्रण पर वहां के राष्ट्रपति यहां आए थे और आगरा में चर्चा हुई थी, उस चर्चा में से अगर कोई चीज या कुछ भी उपलब्धि नहीं हो सकी, कोई परिणाम नहीं निकल सका तो उसका एक प्रमुख कारण था कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से उस दिन घोषणा की कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो भी हिंसा हो रही है, वह एक फ्रीडम स्ट्रगल है। हमने बंगलादेश में मुक्तिवाहिनी को भेजा था और उनकी सहायता की थी। उनका टेलीविजन पर ऐसा बयान एक प्रमुख कॉन्ट्रीब्यूटैंट था, बहुस से फैक्टर्स थे लेकिन प्रमुख कारण यही था।

अध्यक्ष महोदय, हम सोचते थे कि 11 सितम्बर की घटना के बाद अमेरिका के आमंत्रण पर पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल कॉलिशन ज्वाइन करने का निर्णय किया। तालिबान जिस का उन्होंने साथ दिया था, जिस के सहारे उन्होंने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को फैलाया था, उसका उन्होंने परित्याग किया, कम से कम औपचारिक रूप से परित्याग किया। वास्तव में क्या किया, यह सब लोग जानते हैं। हम समझते थे कि शायद उसके कारण उनका कुछ हृदय परिवर्तन हुआ, कुछ चिंतन में परिवर्तन हुआ लेकिन आज श्री अब्दल सत्तार का बयान देख कर मुझे नहीं लगता है कि कोई परिवर्तन होने वाला है। वहां की सरकार अपने क्रैडेनशियल को एक बार नहीं अनेक बार प्रूव कर चुकी है कि हम पाकिस्तान और भारत के बीच स्थायी मित्रता चाहते हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं थी जब प्रधान मंत्री वाजपेयी जी बस में बैठ कर लाहौर गए थे। वह एक असाधारण इनीशिएटिव था। उसके बाद फिर उनको निमंत्रण देकर यहां बुलाया जबकि उन्होंने वहां की चुनी सरकार को हटा दिया था और स्वंय सत्ता में आ गए। हमने कहा कि अगर वह मिलिट्री डिक्ट्रेटर हैं तो कोई बात नहीं, आने दो, बात करेंगे क्योंकि आखिर बात करनी होती है। सारे इनीशिएटिव लेने के बाद भी ये परिणाम लगातार निकल रहे हैं। आज कहते हैं कि दोनों जांच करेंगे, दोनों कैसे जांच करेंगे? जो आतंकवादी मारे गए वे पांचों पाकिस्तानी हैं। उनके एकॉम्प्लिस जो प्रमुख रूप से पीछे लगे थे उन्होंने जैशे-ए-मोहम्मद का नाम लिया। कोई भी सरकार जो सार्वभौमिकता में विश्वास रखती है और मजबूत है, वह ऐसी बात कभी स्वीकार नहीं कर सकती।

अध्यक्ष महोदय, जनरल मुशर्रफ यहां आये थे और तब मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। मैंने उनसे कहा कि आप और मेरे बीच में एक चीज कॉमन है। आप उसी स्कूल में पढ़े हैं, जहां मैं पढ़ता था। इससे आगे मैंने कहा कि मैं अभी- अभी टर्की से आया हूं और मुझे पता लगा कि आपका बचपन टर्की में बीता है और आप तुर्की जुबान बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। मैं टर्की केवल इस्तमबूल और अंकारा देखने के लिये नहीं, मैं तो एक्ट्राडीशन ट्रीटी साइन करने के लिये गया था। अगर एक्ट्राडीशन ट्रीटी की जरूरत हिन्दुस्तान को है तो वह टर्की से नहीं, पाकिस्तान से है। यदि कोई हत्यारा किसी की हत्या कर दे या किसी को किडनैप करके उससे 5 करोड़ रुपया छीन ले, फिर जाकर पाकिस्तान में जाकर शरण ले ले या आपके यहां कोई हत्यारा यहां शरण ले ले तो इस बीच में एक्सट्राडीशन ट्रीटी होनी चाहिये Why not? Why should we not have an extradition treaty? This was his response. But the moment I mentioned, कि 1993 में मुम्बई में बम विस्फोट में 300 लोग मारे गये और उसका प्रमुख अपराधी आपके यहां बैठा हुआ है He immediately changed. उनका ऐटीट्यूड बदला। मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं है। अगर इस बात को प्रमाणित करना हो तो न केवल जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैय्यबा के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी बल्कि दाऊद इब्राहिम और मौलाना मसूद अज़हर जैसे आतंकवादी, जो वहां बैठे हुये हैं और शरण लिये हुये हैं, उन लोगों को वापस यहां भेजना होगा। These are the bases on which whether they are honestly against terrorism or not is going to be judged. ऐसा नहीं कि केवलमात्र यह कह दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं - यहां तक कि शब्दों के प्रयोग में भी इन पांचों पाकिस्तानियों को आतंकवादी न कहकर आर्म्ड इंट्रयूडर्स कहना - जब उन्होने इस घटना की आलोचना की, तब उन लोगों को आर्म्ड इंट्रयूडर्स कहा गया। मैं इस बात

का उल्लेख इसलिये कर रहा हूं क्योंकि सब लोगों ने कहा कि हमारी लॉंग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिये, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिये to deal with this problem of terrorism. हमारे माननीय सदस्य श्री शिवराज पाटील ने कहा कि मैं कई दिन से कह रहा हूं कि वॉर नहीं होना है लेकिन यह टैरेरिज्म चलता रहेगा। चूंकि मैंने जनरल ज़िया का उल्लेख किया कि जब मैं 1978 मे पाकिस्तान गया तो जनरल ज़िया वहां थे। लगभग उसी समय उन्होने अपनी रणनीति घोाित की कि हिन्दुस्तान से हमारे कई युद्ध हुये हैं और हम पराजित हुये हैं। अत; हमें अब नई रणनीति बनानी पड़ेगी और जिसका जिक्र उन्होंने आर्मी कमांडर के बीच मे किया। उसमे उन्होंने कहा कि; "We must adopt those methods of combat which Kashmiri mind can grasp and cope with. In the past we have opted for ham-handed military options and, therefore, failed. "

लेकिन अब हमें political subversion, intrigue के आधार पर करना होगा और A low level insurgency against the regime so that it is under siege but does not collapse as we would not − this is on Kashmir − as we would not yet want Central Rule imposed by Delhi. फिर उन्होंने पंजाब का जिक्र किया। He said, "In brief our plan for Kashmir, which will be code-named as Operation Topac, will be as follows."

श्री शिवराज पाटील ने थोड़ा बहुत अपने भााण में जिक्र किया था कि इस प्रकार की लड़ाई हम कितने सालों से लड़ रहे हैं। इसलिये जब कोई कहता है कि आप युद्ध करना चाहते हैं तो मैं यही कहता हूं कि 3-4 युद्ध हुये हैं और वे सहज हुये हैं।

लेकिन आपरेशन टोपक के नाम से जो युद्ध अब चल रहा है, यह ज्यादा तकलीफदेह है । इसलिए निर्णय करने का सवाल नहीं है । हमें इतना ही निर्णय करना है कि इतने सालों से पाकिस्तान ने जो हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, उस युद्ध का प्रत्युत्तर कैसे देना चाहिए । जैसा हम आज तक देते आये हैं, वह अटैक करता है, हमारे यहां कोई बम विस्फोट करता है, फिर हम उन्हें खोजते हैं और खोजकर उन्हें पकड़ते हैं और दंडित करते हैं । हमें इसी प्रकार से चलते रहना चाहिए या और कोई स्ट्रेटेजी सोचनी चाहिए। खासकर इस बार जब संसद पर उन्होंने हमला किया है। उन्होंने संसद पर हमला करके क्या एक प्रकार से लक्ष्मण रेखा पार की है या नहीं की है, हमें इस पर सोचना होगा। जिस प्रकार से 11 सितम्बर की घटना अमरीका के लिए वाटरशैड बन गई। उससे पहले हम कोशिश करते थे, हम लगातार कोशिश करते रहे हैं। साढ़े तीन सालों में प्रधान मंत्री जी जहां पर गये, विदेश मंत्री जहां पर गये, मुझे भी कहीं पर जाने का मौका मिला तो हम हमेशा उनसे टैरेरिज्म के बारे में कहते थे कि जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत में एक भयंकर स्थिति है। चाहे जिस स्थान पर बेगुनाह नागरिक खड़े हैं, उनकी हत्याएं हो जाती हैं, चाहे वे स्त्री हों, पुरुा हों, बच्चे हों, वे रोज मरते जा रहे हैं। इस मामले में हमें आपका सहयोग चाहिए और उनका सहयोग हमें मिला भी है, ऐसा नहीं है कि पहले हमें उनका सहयोग नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय, अभी किसी ने कहा कि हम आइसोलेट हो गये हैं, इन दिनों कोई हमारा साथ नहीं देता। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी को स्वयं अमरीका के राट्रपति, रूस के राट्रपति, नेपाल के प्रधान मंत्री, भूटान के महाराजा सभी ने फोन करके इस बात की निंदा की और आश्वासन दिया कि टैरेरिज्म के खिलाफ हम आपके साथ हैं। The Foreign Ministers of China, Turkey, Germany, France, Oman are among the many who sent messages. Our External Affairs Minister also had talks on the telephone with the Foreign Ministers of Sri Lanka, Bangladesh and also with the British Foreign Secretary and the US Secretary of State. The Commonwealth Secretary General, the European Union, all of them have condemned it. प्राय: सब लोग कहते हैं - Terrorism cannot be justified on any ground. Including China, all of them said that terrorism has to be stamped out from the whole world.

इतना सब कुछ होने के बाद जैसे प्रधान मंत्री जी ने सुबह कहा कि हमारी समस्या हमें हल करनी होगी। अगर हम यह सोचें कि अमरीका हमारी समस्या हल करेगा, यू.के. हमारी समस्या हल करेगा तो हम ख्वाह मख्वाह अपनी आत्मवंचना करेंगे, यह नहीं होगा। अगर अमरीका का स्वंय पर भरोसा नहीं होता तो वह यह आक्रमण नहीं करता। उन्होंने कोई कोएलीशन के आधार पर भरोसा नहीं किया है, उन्होंने यह अपने दमखम पर किया है। उसी प्रकार से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला हमें करना होगा, यह कोई और नहीं करेगा। लेकिन उसका मुकाबला कैसे किया जाए। किसी ने आलोचना की कि आपके वक्तव्य में वह नहीं बताया, आप लोगों ने वह नहीं बताया। ठीक बात है, हमने नहीं बताया, क्योंकि मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं। यह निर्णय ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे इनपुट्स होंगे। इन्टेलीजेन्स इनपुट्स होंगे, आर्मी के इनपुट्स होंगे, आप लोगों के इनपुट्स होंगे, आम लोगों के इनपुट्स होंगे, इन्टरनेशनल कम्युनिटी के इनपुट्स होंगे और इन सब इनपुट्स को ध्यान में रखकर प्रधान मंत्री जी जिनसे सलाह करना चाहे, उनसे मिलकर फैसला करेंगे। वह फैसला होने के बाद उसके बारे में कुछ बातें होंगी।

15.19 hrs. **(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)**

आप सोचिये कि केवल मात्र 13 तारीख की घटना हो गई, इसीलिए गृह मंत्री अगर बयान करेंगे तो उसमें जब आखिरी पैरा होगा तो उसके बाद हम यह कर डालेंगे, वह कर डालेंगे, यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और बहुत सारे लोगों ने वह नहीं की। इसीलिए इसमें उसका जिक्र नहीं है। क्योंकि जब लोग कहते हैं कि आप कोई भी निर्णय करो, हम आपके साथ हैं। स्वाभाविक रूप से वे यह भी कहते हैं सोच-विचार कर निर्णय करिये। जब वे कहते हैं कि सोच-विचार कर निर्णय करिये, उसका मतलब यह नहीं है कि वे कोई कठोर कदम उठाने के खिलाफ हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं । आज तक हमने आतंकवाद के खिलाफ जो सफलता पाई है, उसमें कठोर कदम तो हैं ही, लेकिन कठोर कदम होते हुए भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय कारगिल का युद्ध हुआ, तब इस सरकार पर सबसे ज्यादा इस बात का दबाव था कि दुनिया भर के इन्टरनेशनल कानूनों और कंवेन्शन के अधीन अगर कोई पड़ोसी अंदर घुस आये तो उसके साथ लड़ाई करते हुए हॉट परस्यूट लेजिटिमेट बात मानी जाती है। आप उसके पीछे-पीछे जाकर, जहां से वह आया है, वहां तक पहुँच जाओ और उसका ठिकाना ध्वस्त कर दो। और यह दबाव भारत सरकार पर कारगिल के समय सबसे अधिक था, खासकर एयरफोर्स के लोग कहते थे कि हमें ऑपरेट करने में कितनी दिक्कतें हैं। आपका निर्देश है कि एल.ओ.सी. क्रॉस नहीं करनी है, एल.ओ.सी. के इस तरफ रहते हुए, इन पहाड़ियों पर हमला करना है, कितना कठिन है, लेकिन कठिनाई के बावजूद भी भारत सरकार ने एक नीति तय की, उसके अनुसार चले। हॉट परस्यूट तब भी लेजिटिमेट था, लेकिन हमने उसका अवलंबन नहीं किया। आज क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं नहीं कह सकता। अनेक फैक्टर्स पर निर्भर है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि 13 दिसंबर और जो कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि -

> "This is the most audacious, and also the most alarming act of terrorism in the nearly two-decades-long history of Pakistan-sponsored terrorism in India. This time the terrorists and their mentors across the border had the temerity to try to wipe out the entire political leadership of India, as represented in our multi-party Parliament "

यानी हद हो जाती। This was the temerity. This was the danger that these brave security men had averted. It could have been a disastrous day in the history of India. I really shudder to think what would have been the consequences if even two of them had managed to come inside. उसको अवॉइड किया है लेकिन अवॉइड करने के बाद हमारे ऊपर जवाबदारी बढ़ गई है और वह

जवाबदारी यह है कि We cannot just regard it as one more terrorist incident. No, it is not. It is far more serious than that और इसकी गंभीरता को पहचानकर ही सरकार जो भी निर्णय करना होगा, वह करेगी। आज अगर देश भर में इसकी चर्चा है और देश भर में एक अपेक्षा है, तो अपेक्षा अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन यह बात भी सही है, स्वयं प्रधान मंत्री जी ने कहा - इस प्रकार के निर्णय केवल भावना के आधार पर नहीं किये जाते, इस प्रकार के निर्णय सारे प्रोज़ एंड कॉन्स सोचकर, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बाद क्या होगा, अगर यह किया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, इन सब पहलुओं पर विचार करके उसके बाद निर्णय किया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सब प्रकार के इनपुट्स प्राप्त करने के बाद ही कोई निर्णय हो सकता है।

अलबत्ता मैं मानता हूँ कि कल और आज की डिबेट इस निर्णय लेने में भी बहुत सहायक होगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ और वह यह कि अगर देश में कोई भी व्यक्ति इस प्रश्न को हिन्दू और मुसलमान की दृटि से सोचता है तो सरासर गलत करता है और भारत की ताकत को कमज़ोर करता है। भारत की ताकत इसमें है कि हमारा देश ऐसा है कि जिस देश में इंडोनेशिया के बाद सबसे अधिक मुसलमान यहां पर रहते हैं, 15-16 करोड़ मुसलमान रहते हैं और बराबरी के साथ रहते हैं, पूरे आश्वासन के साथ रहते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की असुरक्षा का भाव पैदा हो हमारे किसी भी बयान के कारण, यह हमारे ऊपर टिप्पणी है। यह गलत बात है। यह कभी नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं जिन-जिन लोगों ने इसके बारे में कहा है, मैं उनको पूरी तरह से सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह लड़ाई हिन्दू और मुसलमान की नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि यह लड़ाई भारत और पाकिस्तान की भी न हो, यह लड़ाई सभ्य समाज और असभ्य समाज के बीच है। Terrorism is '*asabhyata'*. Terrorism is barbarism. Civilisation *Vs* barbarism is the kind of struggle. और अगर उसका कोई दूसरा पहलू हो सकता है तो वह यह है Democracy *Vs* terrorism. और वह पहलू हो सकता है और डैमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेाता यह है कि हिन्दुस्तान में सौ करोड़ हैं, 110 करोड़ हैं, सबके सब बराबर हैं, यह डैमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेाता है।

उनका धर्म, उनकी जाति, उनका पंथ, कोई भी हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए हिन्दुस्तान के मुसलमान भाइयों को आश्वस्त रहना चाहिए और कम से कम सरकार की ओर से उन्हे अवश्य निश्चिन्त होना चाहिए कि इस प्रकार के चिन्तन को भारतर्वा में कोई स्थान नहीं है। अलबत्ता, मैं देश के मुसलमान भाइयों से भी कहूंगा कि जिस प्रकार से 11 सितम्बर, 2001 की घटनाएं अमरीका में घटीं और उनके लिए ओसामा बिन लादेन एक प्रकार से आतंकवाद का प्रतीक बन गया - अगर ओसामा बिन लादेन की कोई तारीफ करता है, तो वह बेकार ही आशंकाएं पैदा करता है। ओसामा बिन लादेन उसके लिए कितना उत्तरदायी है, यह तो वह जाने, लेकिन कुछ लोग उसके प्रतीक बन जाते हैं और वह प्रतीक बन गया है। जब वह प्रतीक बन गया है तो जम्मू-कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा है, उसके बारे में बहुत से लोग तो काफी अच्छा लिखते रहते हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोग जितने मुखर होंगे, जितनी जोर से अपनी बात कहेंगे, उतना ही कुल मिलाकर समाज में भी विश्वास आएगा और लोग भी आश्वस्त होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान की ये दो बड़ी शक्तियां हैं- लोक तंत्र और सैकुलरिज्म क्योंकि हिन्दुस्तान जैसे देश मेंâ€¦ (व्यवधान) मैं उसकी व्याख्या आज नहीं करूंगा, मैं उसकी बहस में भी नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आज मौका नहीं है, लेकिन अगर किसी दिन सैकुलरिज्म पर बहस करनी है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। यह कोई साधारण बात नहीं है। 1947 में जब हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच तनाव सबसे अधिक था, तब देश का विभाजन हुआ। उस समय कांग्रेस पार्टी विभाजन के खिलाफ थी, लेकिन मुस्लिम लीग के जोर के कारण देश का विभाजन हो गया। डा. अम्बेडकर ने कहा कि जब देश का विभाजन हो गया है, तो एक्सचेंज आफ पापुलेशन भी होना चाहिए, लेकिन हमने उसे नहीं माना। â€¦ (व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : क्षमा कीजिए गृह मंत्री जी, देश के विभाजन के लिए बहुत से लोग जिम्मेदार हैं।â€¦ (व्यवधान)

श्री लाल कृण आडवाणी : आज हम देश के विभाजन की चर्चा नहीं कर रहे हैं। विश्लेाण उसका भी हो सकता है कि देश का विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आज मौका नहीं है।

जिस समय जनरल मुशर्रफ साहब भारत आए थे, उस समय मेरी उनसे वार्ता हुई थी। उस समय मैंने उनसे जिक्र किया कि कैसी विडम्बना है, आपका जन्म दिल्ली में हुआ और आप 54 साल में पहली बार दिल्ली आए हैं जबकि मेरा जन्म कराची में हुआ और मैं 54 साल में एक बार कराची गया। मैंने कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि अब यह स्थिति बदलनी चाहिए। मैंने यह भी कहा कि प्रधान मंत्री वाजपेयी जी के रहते हुए जितना अवसर अब है, उतना पहले कभी नहीं आया और न आगे आएगा। इसलिए उस स्थिति को बदलो। मैंने कहा कि अगर हम स्थिति को बदल पाएं और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लगातार तनाव चलता आया है और युद्ध होते रहे हैं, वे न हों, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे मतभेद होंगे।

जम्मू-कश्मीर के बारे में हमारे मतभेद हैं। मैं पार्लियामेंट का मैम्बर हूं, तो मैं भारत के संविधान के अन्तर्गत पार्लियामेंट का मैम्बर होने के नाते शपथ लेता हूं कि जम्मू-कश्मीर का मतलब, न केवल वह हिस्सा जो इस समय आपके पास है, यानी पाक आकुपाइड कश्मीर वह आता है, बल्कि वह हिस्सा भी आता है जो आपने चीन के सुपुर्द कर दिया है, उसके लिए हम शपथ लेते हैं और मैं यह भी जानता हूं कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, जिनमें आप भी होंगे यह सोचते हैं कि टू नेशन थियोरी के आधार पर पाकिस्तान बना।

जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मैजोरिटी एरिया था, वह हिन्दुस्तान में कैसे गया, उसे तो पाकिस्तान में आना चाहिए था, and you may feel that it is not right that Jammu and Kashmir is with India. But, how are we going to resolve this difference between our perspectives? शिमला में तय हुआ कि हमारे बीच में जो अंतर है, उसे चर्चा द्वारा हल करेंगे, बातचीत द्वारा करेंगे। कल हम आगरा जाएंगे, मेरी यह बात दिल्ली में बात हुई थी। मैंने कहा कि आगरा में जाएंगे, आप वाजपेयी जी से यह तय कीजिए कि we will talk; we will talk; we will talk and talk and try to reduce this gulf between our perspectives. But, meanwhile we shall not be held hostage to the resolution of these differences, यह संकल्प करें। तब उन्होंने तुरन्त कहा कि नहीं, पीस-वीस की बात तो ऐसी है कि वहां आजादी की लड़ाई चल रही है, यह हो रहा है, वह हो रहा है। मोटे तौर पर जहां तक भारत है, भारत देश और भारत की यह सरकार चाहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे हों। लेकिन अगर इस प्रकार का आतंकवाद चलता रहेगा और इस प्रकार के आक्रमण संसद भवन पर होंगे तो शान्ति नहीं हो सकती, उसके लिए फिर कोई न कोई तरीका जरूर सोचना पड़ेगा।

कुछ ऐसी बातें कही गईं जैसे वे आयरन गेट नम्बर एक से आए या आयरन गेट नम्बर दो से आए, वे पांच लोग थे या छः लोग थे, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में, जो जांच कर रहे हैं, वे जानकारी करेंगे। स्पीकर साहब के यहां का सी.सी.टी.वी. एक बात बताता है, दूसरे वर्शन्स दूसरे हैं which do not really relate to the statement that I have made today, but by and large I tell you that it is a matter of great success for the Delhi Police. तीन दिन के अंदर-अंदर उन्होंने इतना खोज निकाला, खोज करके अपराधियों को पकड़ लिया और उसके आधार पर पूरा नक्शा हमारे सामने रखा।